think the Foreign Minister can take up this issue there.

Today we have a lunch hosted by the Chairman for the new Members. So, I will adjourn the House three minutes before for the new Members to reach there. Some of them are here and some of them have already gone.

I also want to make an announcement that all the Zero Hour submissions and Special Mentions which are pending and for which permission has been granted, will be taken up after the Short Duration Discussion. We want to clear all the business that is pending before we adjourn the House *sine die* in two days' time. All the pending matters which the Members feel...

AN HON. MEMBER: What about special mentions?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said that Zero Hour submissions and Special Mentions will be taken up after the Short Duration Discussion so that whatever matters you want to raise about your constituencies are finished before we adjourn the House *sine die* in two days. You should not go back home saying that you wished to raise it.

The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at fifty-eight minutes past twelve of the clock.

2.00 P.M.

The House re-assembled after lunch at five minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri MD. Salim)** *in the Chair.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We will take up Short Duration Discussion.

SHORT DURATION DISCUSSION

The Steep Rise in Prices of Essential Commodities

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब बनी थी लगभग छह माह पूर्व तो उस समय इसे जनता का समर्थन तो था नहीं और एक तिकड़म और भानुमती के पिटारे की तरह तेरह दिशाओं में दौड़ने वाले घोड़ों से खींचे गए रथ की तरह से तेरह दलों की यह सरकार बनी थी परंतु इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वे हम्बल फार्मर हैं, एक विनीत किसान हैं। कांग्रेस पार्टी और जनता दल का समर्थन इस सरकार को प्राप्त है और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। तो लोगों को आशा थी कि कम से कम गरीबों और किसानों का यह सरकार शायद समर्थन करेगी, उनको कुछ राहत पहुंचाएगी। परंतु उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार के छह महीने के काल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जमाखोरों को, मुनाफाखोरों को, दलालों को, बिचौलियों को, पूंजीपतियों को और बड़े-बड़े धन्ना सेठ किसानों को और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गरीबों को, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले लोगों को। सबसे ज्यादा खून चूसा गया है आम आदमी का, किसान का और उसको यह नुकसान पहुंचाया गया। आटे और गेहूं का जो पिछले दिनों स्कैंडल हुआ, जो महंगाई हुई, यह आजाद हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा घोटाला है। इससे पहले आटे और गेहूं की कीमतों में इतना बड़ा घोटाला, इतना भ्रष्टाचार और इतना निकम्मापन किसी सरकार ने नहीं दिखाया। इन पिछले दो महीनों में ही गरीब आदमी की जेब से करीब पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि निकल गई और बड़े-बड़े जमाखोरों के पास पहुंच गई। मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि रुपए की कीमत जैसा कि अखबार में पिछले दिनों आया था, 5.9 पैसे रह गई है क्योंकि यह सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती। यह तो 1962 के बाद, बेस ईयर 1962 को मानकर, यह 5.9 पैसे रह गई। यह सरकार तो छह महीने की है लेकिन इस समय जो होलसेल प्राइस इन्डेक्स है वह 6.8 परसेंट है और जब यह सरकार बनी थी तब यह 4.77 परसेंट था। तो 4.77 परसेंट छह महीने के अंदर होलसेल प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है परंतु होलसेल इन्डेक्स हिंदुस्तान के आम आदमी की कीमतों का कोई आईना नहीं है। यह उसका कोई शीशा नहीं है। वह है कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स और कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स, अक्टूबर के महीने का जो

इन्फ्लेशन का रेट है वह 27.4 परसेंट है। इतना तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में वर्स्ट से वर्स्ट पीरियड में, जब हिंदुस्तान में अकाल पड़ा था, तब भी कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स इतना ऊपर नहीं गया था। पिछले साल अक्टूबर 95 में यह 313 था और अक्टूबर 96 में यह बढ़ कर 398 तक पहुंच गया, यदि बेस ईयर 82 को माना जाए। 85 प्वाइंट उसमें बढ़ कर 27.4 परसेंट इनक्रीज़ हुई और यह फर्क इसलिए पड़ता है कि अमीर आदमियों की चीजें सस्ती हो रही हैं। अमीर आदमी के यूज़ की जाने वाली चीज़ें जैसे फ्रिज, कारें, एयर-कंडीशनर की मार्किट में कोई डिमांड नहीं बची, पैसा नहीं बचा और शेयर प्राइसेज गिर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं और इन हालात में अमीर आदमी की चीज़ें सस्ती होने से होलसेल प्राइस इन्डेक्स 6.8 परसेंट है और कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स 27.4 परसेंट है। सितम्बर और अक्टूबर के बीच में यह जो कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स की फिगर्स हैं मेरे पास, अकेले एक महीने में उसके अंदर 18 परसेंट इनक्रीज़ हुई है। 339 था सितम्बर में और अक्टूबर में 398 था कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स, लेबर ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स, बेस ईयर 1982। गरीब आदमी के ऊपर ऐसी भयंकर मार, ऐसी महंगाई और उसके बाद भी यहां कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और सिवाय आटे के और किसी चीज़ के दाम में फर्क नहीं पड़ा। पिछले 6 महीने में आटा 6 रुपये से 12 रुपये किलो हो गया, 800 ग्राम की डबल रोटी 6 रुपये से बढ़कर 12 रुपये मिल रही है। 100 प्रतिशत इन्क्रीज़। 6 रुपये की डबलरोटी 12 रुपये में मिल रही है। गरीब आदमी सुबह उठकर चने के साथ और डबलरोटी के साथ गुजारा करता है जो अपने घर में खाना नहीं बना सकता। आलू पिछले साल इस मौसम में 2 रुपये किलो था और वह अब 12-13 रुपये किलो है। पत्ता गोभी दो रुपये से 8-9 रुपये किलो हो गयी है। टमाटर चार रुपये था और अब 16 रुपये किलो है। सब्जियों के दाम 5-6 गुणा बढ़ गये हैं। दालों में 60 फीसदी की बढ़ोत्तरी पिछले 6 महीने में हुई है। चने की दाल 11 रुपये किलो थी, अब 20 रुपये किलो है। राजमा 18 रुपये किलो से बढ़कर 32 रुपये किलो हो गया है। मूंग 14 रुपये किलो थी, अब 26 रुपये हो गयी है। सरसों का तेल 28 रुपये से बढ़कर 38 रुपये हो गया है और इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। किसानों से आपने गेहूं 3 रुपये 80 पैसे या 4 रुपये 15 पैसे ले लिया और इस समय बाजार में यह 10 रुपये किलो बिक रहा है। उसके हाथ से तो गेहूं निकल गया है। जो बड़े-बड़े किसान है, जिन्होंने ज़माखोरी कर ली है, सिवाय उनके बाकी सबको इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़ी हुई यह सब्जियां जो बाजार में आ रही हैं या दालों के भाव बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, कोई अकाल नहीं पड़ा, मानसून फेल नहीं हुआ। जब अकाल नहीं पड़ा, मानसून फेल नहीं हुआ, जब मानसून अच्छा हुआ तब इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? मुझे अपने खाद्य मंत्री का वक्तव्य बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैंने टी०वी० पर सुना, वह कहते हैं कि "यह जो जमाखोर हैं, इन लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची है।" उन्होंने तो साजिश रची है, ठीक है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने इसमें फायदा उठाया है, पर आपने क्या किया है? Were you only a silent spectator? आप इसके अंदर क्राई कर रहे हैं। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं कि उनकी पूरी क्राईवेंसी They were not only silent spectators, but they also connived with them. उन्होंने इसके अंदर पूरा इनको मौका दिया है और उसके कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इस बात को देखें। एक पहला वक्तव्य सरकार ने आते ही दिया है "हम पी०डी०एस० से सिर्फ गरीबी की रेखा के नीचे वालों को राशन देंगे, बाकियों को राशन नहीं देंगे।" एक वक्तव्य दिया "कीमतों पर गरीब आदमी को 50 परसेंट सब्सिडी देकर सामान दिया जाएगा।" जब आपने बयान दिया तो उसके बाद आपने कुछ किया तो नहीं। राम विलास पासवान जी का मैंने बयान सुना। यह कहते हैं कि कैबीनेट में इसका बहुत भारी विरोध हो रहा है और कैबीनेट में अलग-अलग, डिफरेंस आफ ओपीनियन है इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। आपने तो यह नहीं किया पर लोगों ने, बड़े किसानों ने, जमाखोरों ने और दलालों ने यह सोचा कि अब केवल 5 परसेंट, 10 परसेंट, 19 परसेंट गरीबी की रेखा के नीचे लोग मानते हैं, उनको छोड़कर बाकी सब तो खुले बाजार में आएंगे। उन्होंने उस सारे सामान को स्टोर कर लिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मार्च महीने में आपसे कहा गया कि इस साल 31 लाख टन कम गेहूं की खरीद हुई है। यह ठीक है कि इस साल करीब 31 लाख टन फसल कम हुई और 41 लाख टन कम हमने खरीद की। क्यों कम खरीदी? बाजार में लोगों ने आपको अनाज क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि उन्हें यह लगा कि बड़ा अच्छा मौका है, अब इसमें खुले आम पैसा कमाएंगे और सरकार ने तो अब राशन खत्म कर देना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म कर देना है। इसलिए उन्होंने जमाखोरी करते-करते अपने भंडार भर लिए और आप बैठे रहे। जून तक ऐक्सपोर्ट होता

रहा। यह ठीक है कि आप जून में आए। यह पिछली सरकार की जिम्मेदारी थी किन्तु उन्होंने ऐक्सपोर्ट किया, सब्सिडाइज्ड रेट पर ऐक्सपोर्ट किया। दुनिया के बड़े-बड़े लोग आ गये, बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ गयीं, यहां से अनाज खरीदती गयी और ऐक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने यहां पर अड्डे खोल दिये। आपने जून महीने में यह सब क्यों नहीं रोका? चलिए छोड़ दीजिए। आप जून में आए। जून के बाद फूड कारपोरेशन ने कहा, मिनिस्टरी ने कहा, सबने कहा कि इस साल खरीद कम हुई है, इस संबंध में कदम उठाइए, ऐक्सपोर्ट मत होने दीजिए किन्तु सितम्बर के महीने में आप आटा ऐक्सपोर्ट करते हैं। सितम्बर के महीने तक आटा ऐक्सपोर्ट होता है। आपने जून के बाद उस पर रोक क्यों नहीं लगायी? आपने फ्लोर मिलों को, रोलर मिलों को कंट्रोल रेट पर गेहूं दिया, सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया, पांच रुपये के हिसाब से दिया। उन्होंने आटा एक्सपोर्ट किया आठ रु०, नौ रु० और दस रुपये में। आटा एक्सपोर्ट होने लगा तो यहां पर आटे की कमी होने लगी। आटे की कमी क्यों नहीं होती, आपने सितम्बर के महीने तक आटे का एक्सपोर्ट जारी रखा और खुली छूट दी कि इसका एक्सपोर्ट करते रहे। यह कहकर कि हम मार्किट में प्राइज को कम करना चाहते हैं, खुले बाजार में पांच लाख टन गेहूं देना शुरू कर दिया। वह पांच लाख टन गेहूं कहां है? रोलर मिलों ने गेहूं तो ले लिया पर आटा उस तय भाव से नहीं बेचा आपसे गेहूं लिया पांच रुपये के हिसाब से और बाजार में बेचा दस रुपये के भाव पर, मैदा बेचा 15-20 रुपये के भाव पर। मैदा, सूजी और जो चीजें रोलर मिलों से निकलीं उनको आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया? जिस भाव पर आप दे रहे थे उनसे उसी तय भाव पर क्यों नहीं लिया? उनसे उस भाव पर नहीं लिया गया। पांच रुपये में एक किलोग्राम का फायदा, एक टन में पांच लाख टन का फायदा और करीब-करीब आप दे रहे हैं पांच लाख टन। 250 करोड़ रुपये उनको एक महीने में मुनाफा कमाने की इजाजत दे रहे हैं। आप चुपचाप बैठे रहे, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपने तीन कदम उठाये हैं पहले कदम के अंतर्गत कंज्यूमर्स एसेंशियल कमोडीटीज एक्ट को लागू किया, दूसरा आपने बीस लाख आयात करने का फैसला किया तीसरा आपने रोलर मिलों से कहा कि आप भी इम्पोर्ट कर लें। Why have you not taken this action earlier? सितम्बर में यहां जीरो आवर में इसको उठाया गया या अक्तूबर में जीरो आवर में फिर वही मेन्शन किया गया सारी की सारी एजेंसियां आपके गले पड़ रही थीं कि महंगाई बढ़ रही है। स्टेंडिंग कमेटी में इस सवाल को उठाया गया था। अब आप दिसम्बर के महीने में यह एक्शन कर रहे हैं, दिसम्बर के महीने में यह कह रहे हैं कि हां ये कदम उठाने चाहिये। आपने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाये? आपने पहले ये कदम इसलिये नहीं उठाये ताकि यहां पर आर्टिफिशियल स्केयरसिटी कर दें, क्योंकि कोई स्केयरसिटी नहीं थी। आज भी अगर आप फिगर्स को देखें तो जो हमारे पास स्टॉक था पिछले साल वह 8.4 मिलियन, तकरीबन आठ करोड़ टन था। इस साल हमने इसमें 8.1 मिलियन टन और इंक्रीज कर दिया है। 17.7 मिलियन टन हो गया जबकि जरूरत 9 मिलियन टन की थी। इसमें से आठ-नौ लाख टन बचेगा। आपने एक्वायर दस परसेंट भी नहीं किया। बाकी सारा हिन्दुस्तान में लोगों के पास, जमाखोरों के पास पड़ा हुआ है। उसको निकालने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया। उसके लिए आर्टिफिशियल स्केयरसिटी कर दी। अब आप कह रहे हैं कि हम इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने में सीरियसली सोचना चाहिये कि इम्पोर्ट करने की जरूरत है भी या नहीं? अप्रैल महीने में किसान के पास फसल आ जायेगी, आप उसको तो देते हैं 4 रुपये 15 पैसे और इम्पोर्ट करके बाहर के किसान को देंगे सात रुपये। उसको सात रुपये पर देने को तैयार हैं और अपने किसान को भी इतना पैसा दें तो इस कीमत पर हिन्दुस्तान में कई करोड़ टन अनाज बाहर निकल सकता है, परन्तु आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने इसमें आर्टिफिशियल स्केयरसिटी कैसे क्रिएट की, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। किसान की आज हालत क्या है? किसान ने तीन रुपये 80 पैसे में आपको बेचा। छोटा किसान अब जब अपना बीज बो रहा है तो उसको बीज खरीदना पड़ रहा है आठ रुपये, नौ रुपये, दस रुपये। अपना ही गेहूं बेचकर अपना ही बीज खरीद रहा है।

यूपी में गन्ना सड़ रहा है। गन्ने को किसान जला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एनाउंसमेंट की थी कि बकाया राशि आ जायेगी, हम डी-लाइसेंसिंग कर देंगे और उसका रेट बढ़ा देंगे क्योंकि गन्ना सड़ रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना नहीं बोयेगा, देश का दूसरा किसान गेहूं नहीं बोयेगा। हालात यह हो गई है आज आपने किसान के कैश क्रॉप्स को एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया है और यह कहा कि कैश क्रॉप्स एक्सपोर्ट हो सकती है। एक्सपोर्ट के लालच में जो फिलिपीन्स ने किया, जिम्बाबवे ने किया, मेक्सिको ने किया उस लिहाज से सब चीजों की कमी हो गई और जैसे वहां पर उनको कैश क्राप्स इम्पोर्ट करना पड़ा वैसे ही आप हिन्दुस्तान में

भी ये हालात पैदा करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि स्थिति सुधारी जाए, उस स्थिति को इस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। यहां पर मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। एक तो इन्होंने कहा कि यह शरारत बड़े-बड़े जमाखोर कर रहे हैं और वे साजिश कर रहे हैं। आप इस साजिश को रोक नहीं पाए। Is it not your failure?

दूसरा यह कहते हैं कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मैं थोड़े जिम्मेदार हूं। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ऐसी पोलिटिक्स आप खेलते हैं। कोई सीमा होती है गलतबयानी करने की, बेईमानी की कोई सीमा होती है। क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने गेहूं इम्पोर्ट करना है?

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, बेईमानी वह अन-पार्लियामेंटरी है। इसको रिकार्ड से एक्सपंज किया जाए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने "असत्य बात" कही थी। बेईमानी शब्द मैं वापस ले रहा हूं।

श्रीमती कमला सिन्हा: आपने "असत्य बात" कही होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप यह शब्द नहीं कह सकते।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैं वह शब्द वापस लेता हूं। I take back my word. मैंने यह कहा कि असत्य बोलने की भी कोई सीमा होती है। क्या दिल्ली गवर्नमेंट को बाहर से इम्पोर्ट करना था? क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने खुले बाजार में अनाज बेचा? क्या आपने दिल्ली गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करने की इजाजत दी थी? दिल्ली गवर्नमेंट को एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट को लागू करने की इजाजत दिसम्बर महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोलिटिक्स किस सीमा तक खेला जा सकता है और यह सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है, केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा है। दिल्ली को गेहूं मिलेगा हरियाणा से, यू०पी० को मिलेगा राजस्थान से, बिहार को मिलेगा मध्य प्रदेश से। यह क्या मजाक है। दिल्ली में आपके 6 स्टोर हैं। लेकिन सारे खाली पड़े हुए हैं। रेलवे रैक्स नहीं मिलते। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और खाद्य मंत्री ने 7 सितम्बर और 17 नवम्बर को लिखी कि क्या हमें 35 हजार टन आप दिसम्बर महीने में दे रहे हैं। हमारी डिमांड है 60 हजार टन की और 40 हजार टन हम उठा सकते हैं। आप कहते हैं कि 30 हजार टन हरियाणा से लेकर आओ। दिल्ली में 6 गोदाम हैं लेकिन आपने इन गोदामों को खाली कर दिया और कहते हैं कि हरियाणा से लाओ। रेलवे अवेलेवल नहीं, कैसे लाओ, ट्रक से लाओ। ट्रक से लायेंगे तो उस पर कितना भाड़ा पड़ेगा, कीमत कितनी बढ़ेगी, गरीब आदमियों पर उसका कितना भार बढ़ेगा। आप यह कह रहे हैं कि 30 हजार टन हरियाणा से लाओ। प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी जा रही है। खाद्य मंत्री की चिट्ठी 7 तारीख को गई। आज 18 तारीख है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब तो दीजिए कि दिल्ली के लिए हरियाणा से कैसे लायेंगे। कौन सा तरीका है और कितने ट्रक उसको जाकर ला सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया, सुपर बाजार जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और जो कंज्यमूर स्टोर्स हैं, इन्होंने उनको थोड़ी-थोड़ी आटे की थैलियां दे दीं। लेकिन दिल्ली के कंज्यूमर्स स्टोर्स को नहीं दी, दिल्ली के फ्लोर मिल्स को नहीं दी और वहां पर पोलिटिक्स खेलने की कोशिश की। क्योंकि इस संस्था के चेयरमैन जनता दल के हैं, उसके मेंबर जनता दल के आपने अप्वाइंट किऐ हुए हैं, आपने उनको कहा कि आप अपने वरकर्स को आटा देकर झुग्गी-झोंपड़ियों में भेजें और यह कहें कि यह तो हम कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट यह सब इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि आप उसको गेहूं नहीं दे रहे हैं। आप बहाना बनाते हैं कि मई में आपने उठाया नहीं। महोदय, मई में 4.17 पैसा प्रति किलो राशन में था और 4.17 पैसा ही बाजार में था। ऐसी स्थिति में कोई राशन की दुकान से क्यों लेता। उस समय कोई राशन की दुकान से लेने के लिए तैयार नहीं था तो उस समय उसको उठाने की क्या जरूरत थी। लेकिन दिसम्बर महीने में जब स्थिति ऐसी हुई, स्टार्व हुई और उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति है इसको जानबूझकर किया जा रहा है। आज हालत यह हो गई है कि कालाहांडी में लोग भूख से मर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वहां के चीफ मिनिस्टर 15 हजार आदमियों का खाना करते हैं और तीन साला जश्न मनाते हैं और वहां के आदिवासी दुकानें लूट रहे हैं। सारे हिन्दुस्तान में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जितना पिछले 6 महीनों में बरबाद हुआ, इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी बुरी हालत में गरीब आदमियों को इस महंगाई के अंदर जीना पड़ रहा है। आपकी जो पे कमीशन की रिपोर्ट आनी है वह नहीं आ रही है और दूसरी तरफ छंटनी हो रही है, मजदूर निकाले जा रहे हैं, मिलें बंद हो रही हैं। मेरे पास आंकड़े हैं कि कितने

हजार मजदूर इस साल पिछले 6 महीनों में निकाले गए हैं। फैक्टरियां बंद हो रही हैं, मजदूरों को निकाला जा रहा है। ऐसी हालत में किसानों और गरीबों के नाम पर बनने वाली सरकार ने सब से ज्यादा जो न्याय किया उन्हीं लोगों के साथ किया है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि एक तो पहले इस बात को देखें कि इम्पोर्ट करने में भ्रष्टाचार हुआ है और होने वाला है क्योंकि हमेशा ही हुआ है। पहले चीनी का भी हुआ उसमें सुख राम जी और दूसरे मंत्री गये थे। इसमें कौन मिनिस्टर जाएगा, मुझे मालूम नहीं परन्तु 20-20 डालर ज्यादा कीमत दे कर इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको आप देखें। फिर कितना भी अनाज हिन्दुस्तान में आप पैदा कर लें, कितने भी ज्यादा हम सेल्फ सफिशियेंट हो जाएं, ईश्वर न करे कि ऐसा दुर्भाग्य हो कि एक मॉनसून फेल हो गई तो क्य हालत होगी, इसकी कल्पना भी आप कर लीजिये। पापुलेशन कंट्रोल पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। बढ़ती हुई पापुलेशन को रोका नहीं जाएगा तथा पापुलेशन कंट्रोल के लिए जितना पैसा रखा गया था फेमली प्लानिंग के लिए जो पैसा रखा गया था, इस साल उसको भी कम कर दिया है। सरकार की इसके बारे में कोई नीति नहीं है। शायद आपको अपने वोट बैंक पर प्रोब्लम दिखाई दे रही है, इसलिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर पापुलेशन एक्सप्लोज़न ऐसे ही चलता रहा तो हिन्दुस्तान का किसान चाहे कितना भी उत्पादन बढ़ा ले अंततः इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आप अपनी किसान विरोधी नीतियों को ठीक करें, पॉलिटिक्स न खेलें और हिन्दुस्तान के गरीब आदमी के लिए आने वाले दिनों में काफी अनाज है, यह हिन्दुस्तान के अन्दर ही पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालें ताकि गरीब आदमी को राहत मिले। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Dr. Manmohan Singh. ... Not here. Shri V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the very important subject of price situation in the country. Sir, this price rise is very much affecting, especially, the common man, the farmers, salaried classes and industrial workers.

Earlier when the issue was raised in this House that wheat was not available in the capital city of Delhi, the Minister made a long statement here, and from the statement I have found that the Minister himself has admitted that the price of wheat has been increased by the present Government, when they came to power, to the tune of Rs. 150 per quintal. ...*(Interruptions)*... You have not taken into account the freight charges which are also there. The statement of the hon. Minister is there. If he goes to the South, he will find that there is an increase of Rs. 150 per quintal in the price of wheat there.

Sir, the hon. Minister has said that they are revamping the Public Distribtuion System and trying to reach the people, but it did not cut much ice and the hon. Members were not convinced. My hon. colleague and a senior Member of this House, Prof. Vijay Kumar Malhotra, while moving the motion for raising this discussion on the price situation, was quoting the wholesale price index, the consumer price index and the inflation—which has been remaining normal, or even stagnant—which has been very minimum for the last four, five months. But, so far as the ground realities of the prices of essential commodities are concerned, all of us who are sitting in this House are well aware of the fact that the price of wheat, especially of *atta*—I would like to specifically take up *atta* which has been a matter of concern not only to the people of Delhi but the entire country—which was Rs. 6.50 per kg. about four, five months back, has now gone up to Rs. 14-15 per kg. in the open market. Rice, which is the common man's item of food and which used to be sold at Rs. 7-8 per kg., in the South, is now selling at Rs. 25 per kg. About edible oil, especially the palm oil which is being consumed nowadays, was being sold at Rs. 28/- per kg. Even under the Public Distribution System it is being sold at Rs. 29.50 P., and outside it is sold at Rs. 30/- or Rs. 35/-. Then, the quantity of ground-nut oil and the coconut oil being produced in the country is not sufficient. Now the Government is

thinking of importing them. The price of coconut oil has gone up beyond Rs. 52 per kg. It was sold at Rs. 32/- or Rs. 33/- per kg.

Steel is used for the purpose of construction of houses. Its price has gone up by 40 per cent. The price of cement has doubled. It was sold at Rs. 145/-. Now it is sold at Rs. 185/- or Rs. 190/- per bag.

Then, take the case of sugar. Sugar is the only item, the price of which is being maintained.

The hon. Member has mentioned about potatoes. I have mentioned about the coconut oil.

The price of pulses has doubled. There is 100 per cent increase in its price.

Let the hon. Minister give us the wholesale price index and the consumer price index and say whether there is any correlation between these indices and the price-rise.

There is no correlation. The ground reality is that as far as the items that are sold in the market are concerned, their prices have doubled. The common man is feeling the pinch of it. The hon. Minister has to accept this. I know that after some time it is going to be the harvest season. I admit that for some time there will be the lean period.

But, what has the Government done for the purpose of controlling hoarding and black-marketing? That is the thrust area. I am not blaming this Government or any other Government. Every Government says, "We are taking all measures to contain or even to control hoarding and black-marketing." But that is not happening. No State Government is able to do that. The Central Government is not serious about it. Unfortunately, there is one political party in this country, which is being backed by businessmen. Those businessmen who are supporting that party...

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Which party?

SHRI V. NARAYANASAMY: If you ask, I say it is the BJP. I openly say that it is the BJP, and the businessmen who are hoarding and black-marketing are in the BJP.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I take strong objection.

यह बहुत ही गलत स्टेटमेंट है।

This type of statement should not be made. He says, "Take action." Why don't they take action? ...*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: I am asking the Minister to take action against the BJP—supported businessmen.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): देखिए, आप भी कुछ बोल सकते हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं, चाहे किन्तु जो कुछ बोलेंगे उसका तो विरोध होगा। इसलिए जरा आप संभालकर बोलें। आपके पास भी सब ट्रेडर्स हैं, बी०जे०पी० का कोई सिक्का लगा हुआ नहीं है...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: Seventy-five or eighty per cent belong to the BJP. Therefore, I am saying that.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Seventy per cent are in the BJP, and thirty per cent are in the Congress.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: ब्लैक मारकेटियर, जमाखोर सब कांग्रेस के हैं...(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: The communist parties are not getting them because nobody wants to join them.

I want to ask of the Minister in a pinpointed manner: what steps are you taking to contain or even to arrest black-marekting and also hoarding by businessmen who have done so for the purpose of creating an artificial crisis of shortage of foodgrains and pulses in the country? The hon. Minister will come with a stock reply. I am not going to be convinced by that. He will say, "I have written to the State Government concerned." I know that it is a subject of the State Government, but, since you are giving consignments to them for the Public Distribution System, you have got every authority.

You have to tell the State Governments to tighten the control when there is hoarding and black-marketing.

You tell the State authorities to tighten the machinery and bring out the items that have been hidden by the traders for the purpose of creating an artificial crisis in the country. Sir, I give an example on which Mr. Malhotra was fighting with me.

SHRI NARENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Nobody is fighting. Who can fight with you?

SHRI V. NARAYANASAMY: That is all right. I am thankful to Narendra Mohan Ji. Sir, the hon. Minister made an announcement that he was going to import two million tonnes of wheat for resolving the crisis. Sir, who made the hue and cry? It is the businessmen of Delhi who opposed it. Why did they do it? It was because they wanted to maintain the price rise in such a way that they can loot the people of this country. They know when the imported wheat comes, the price will fall. Therefore, they say, 'do not import'.

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: They are importing at Rs.7 per kilogram and they will sell it at Rs.8 per kilogram.

SHRI V. NARAYANASAMY: That is a different matter.

SHRI NARENDRA MOHAN: That is the main argument. After all, at what price is the wheat going to be sold? That point you have to see. If you buy wheat at $167 or $165 per tonne,...

SHRI V. NARAYANASAMY: I know that. You have raised the issue in the House. I am coming to it. Sir, the association of the traders of Delhi and some parts of the country have issued a statement saying that the Government should reconsider the decision on import of wheat. Everybody knows that they are hoarding the wheat and are selling it in the black market. Why are they making such a statement? Let the wheat hoarded by them be sold in the open market.

SHRI NARENDRA MOHAN: Sir, he should not hold any brief for the traders of Delhi *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Narayanasamy, kindly come to the point about the rise in prices of essential commodities.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I hold the same view that wheat should be purchased by the Government at a competitive price, but, without listening to the second part of my argument, they are raising their voices. This is the problem with the BJP Members.

Now, let me come to the public distribution system on which the hon. Minister spoke earlier. Several times we pleaded with the Government, and I made the plea in the House also that there should be rationalisation in the public distribution system. My point is, why do you give ration at subsidised rates to rich persons also? Kindly categorise the people. You brought in the green card system. You implement it. Whenever this issue was raised, I pleaded not to give it to the 15 or 20 per cent of the population, which has got the purchasing power to purchase them in the open market. You give it to the people who are below the poverty line or those who belong to the salaried class and are at the lower level of salary. You give ration to the workers. But, why do you give it to the I.A.S. Officers? Why do you give even to the Members of Parliament? You cut it from the rich class and give it to the poor. I would also urge upon the hon. Minister to revamp the public distribution system. When the consignment is taken to the place for distribution, 30 per cent of the consignment is not given, but is sold in the black market by the ration shopkeepers. Why are you not controlling it? The Minister in his reply will say that he has allocated tonnes of wheat to the States. Yes, but he has to have a fool-proof system by which wheat, edible oil, kerosene etc. go to the people who are really in need of it. My question

is what mechanism are evolving to ensure that they reach to those who are really in need of it. Why are you giving it to the rich? They are not using it. That is being sold by them at a higher price in the black market. Why is it happening?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Kindly conclude. There are three, four more names from your party.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will take three, four minutes. I would like to give comparative figures. When a farmer takes his commodity to the market for the purpose of selling it, he sells it at a very low price. But the person who purchases his commodity, generally stores it, and sells it at a much higher price in the market. Thereafter, if the same commodity is further refined or modified into some other product, and is finally brought in the market, the price goes up by four times. Therefore, there is a system failure. So, you are not able to control prices with the help of present system. When *atta* is being sold in the open market at Rs.15/- per kg., you did not take any step. What have you done? What action have you taken? I blame the Government of Delhi also. They should have known well in advance as to how much wheat they require for the State of Delhi. They should have informed the Central Government about the steps taken by them for procuring wheat. But they have not done it. All of a sudden, when the price of *atta* was raised. The State Government of Delhi started shouting. The State Government should have apprised the Central Government about the real situation well in advance. They should have demanded more wheat from the Central Government. They have not done it. There was a bumper crop of wheat when the Congress Government was there and we had sufficient stock of wheat. More than 38 lakh tonnes of stock was there even after export. Why has the quantity depleted? Why have you not been able to bring more wheat in the open market for the purpose of Public Distribution System? The Central Government has not been able to do it. Why have they failed? The Central Government has to be a watch dog. *(Interruptions)* The Central Government should act as a watch dog for controlling the prices. They should monitor the price situation very closely and should issue directions to the State Governments for revamping the Public Distribution System, from time to time. I charge that the Central Government has completely failed in monitoring the Public Distribution system properly. The State Government is not solely responsible for this lapse. The responsibility of the Central Government in this regard is much more. But the State Government should also share the responsibility.

Now, I am coming to the last point, and with this submission, I will conclude. The general price situation is creating an alarm in the minds of people. There are many reasons for it. The hon. Finance Minister is expected to be here. He is the right person to answer all the points that have been raised in respect of the price situation. The hon. Minister of Food and Civil Supplies will not be able to answer the points raised in respect of the economic situation.

Now, as far as our country is concerned. I would like to inform the House that exports have been reduced, a large number of people are without jobs and imports are increasing. Apart from that, due to inflation, devaluation of rupee has further started and as per the reports, the value of one rupee is equivalent to eight paise. Apart from that, the hon. Minister of Railways has admitted that the Indian economy is sitting on a volcano. This is the situation. Under the present circumstances, who are the affected people? The common man, who is the bread-winner of his family, and who is getting Rs. 10/- or Rs.20/- per day, as his wages, is the real sufferer. He has to maintain himself and his family with this meagre amount. He has also to educate his children with this meagre amount. So, he is the real sufferer. But this Government is

keeping quiet. They say that by resorting to import, they are going to reduce the price of wheat. But that is only with regard to wheat. What about rice. You see, people in the southern and the eastern part of the country eat rice. What are you going to do for them? There are floods, cyclones and hurricanes in those States. The present crop has been destroyed due to floods and cyclones. Now, rice is going to be sold at the rate of Rs.35/- per kg. Naturally, people will have to starve. An alarming situation is being created now. I do not know whether the hon. Minister is proposing to take certain steps to help those States. What spteps is he proposing to help the people of those States? Now, a threat is coming. They say they are going to increase the price of petroleum products like petrol, diesel, etc. That is going to kill the people. They had increased the price before the budget session. We had raised a hue and cry in this House and the Prime Minister had given an assurance on the floor of this House that there was not going to be any further increase. If they increase the price of petroleum products, petrol will be sold at Rs.40 per litre. The consequences of that will be an increase in the cost of transportation, in the prices of pulses, vegetables, grains, etc. Ultimately, the people will not have the purchasing power. We will be seeing another Romania in this country. Inflation rate will go up to 4000%. This is what we are going to have. It would be better if the hon. Minister tells the Prime Minister to take immediate steps to call a meeting of the Chief Ministers of various States and to control the price situation. Otherwise, this Government will be thrown out by the people.

श्री नरेश यादव (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदय, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में वृद्धि के संबंध में हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके साथ ही साथ जिन साथियों ने इस मूल्य वृद्धि की चर्चा को यहां लाया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत जब बढ़ती है तो देश की आम नागरिक परेशान होता है क्योंकि उसके पेट से सीधा संबंध है और इसलिए उन लोगों का उदेलित होना, आम लोगों का उदेलित होना स्वाभाविक है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब महंगाई के पीछे राजनीति की बदबू मालूम पड़े तो चिंता थोड़ी जरूर बढ़ जाती है क्योंकि जब जब गरीबों की सरकार और किसानों की सरकार इस देश में बनी है तब तब न जाने क्यों जमाखोर, काला-बाजारी लोगों ने षडयंत्र करके उस सरकार को गिराने का उपक्रम किया है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब जब इस देश के प्रधान मंत्री बने थे तो यहां के कालाबाजारियों ने, जमाखोरों ने एक स्कैण्डल पैदा किया था और वह स्कैण्डल था प्याज का। उस प्याज के स्कैण्डल के चलते उन्हें सरकार से जाना पड़ा था। आज भी एक स्कैण्डल हो रहा है, पूरे देश के जमाखोर और पूंजीपति, जो कालाबाजारी हैं, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, षडयंत्र के तहत एक साजिश की है पूरे देश में, कि कैसे गरीबों के वोट से चुनी हुई इस सरकार को बदनाम किया जाए। इसका प्रमाण हमारे सामने है, जो मैं आपके सामने देना चाहूंगा। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी है आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण करने की। केन्द्र सरकार, प्रोक्योर करती है, स्टोर करती है और पी०डी०एस० खाद्य निगम के गोदामों से लेकर वितरण करती है। इसके बाद बाकी मुहैया करने का काम आम जनता तक पहुंचाने का काम, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य के हिसाब से क्या एलोकेशन आपने दिया था? उस राज्य ने कितना उठाव किया, कितना आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उठाया? स्टेटवाइज ब्यौरा हमें चाहिए, जिससे सामने दिखाई पड़े कि कितना राज्यवार उसके हिसाब से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उठाया गया? जब वह उठाया गया तो उसका वितरण क्यों नहीं किया गया और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? महोदय, इस बात की जानकारी हमें आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, गरीबों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, जो बहुतायत संख्या में हैं, उनके लिए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था आपने की। अब चूंकि अधिकतम लोगों के पास यह सामान नहीं जाता है, जबकि न्यूनतम आदमी अधिकतम अनाज को जमा कर लेता है। और इसी तरह से जब न्यूनतम व्यक्ति अधिकतम माल को

जमा कर लेता है तो माननीय मंत्री जी ने एक स्टैप उठाया और देखा कि कैसे अधिक से अधिक लोगों के पास आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को पहुंचाया जाए। तो जिन व्यक्तियों पर इसका सीधा जोर पड़ा और जिन पर यह करारा हमला था माननीय मंत्री जी के द्वारा, वे और पूरे देश के जमाखोर इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक साजिश की और इस साजिश के तहत उन्होंने एक कृत्रिम महंगाई पैदा की। कोई महंगाई कहीं नहीं है, यह बनावटी महंगाई है। इस कृत्रिम महंगाई को पैदा करके केवल एक हा-हाकार पैदा करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह है कि निश्चित तौर से जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का वरदहस्त है, किसका है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के साथ-साथ यह जानना चाहता हूं कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो कालाबाजारी हैं, जमाखोर हैं? बताना होगा इस सदन में आपको कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नारायणसामी जी ने अभी 14.00 रुपए किलो आटा कहा, लेकिन नारायणसामी जी के कहने से मेरे कहने तक अंतर हुआ और अंतर यह है कि 14.00 रुपए किलो उन्होंने कहा और मैं कह रहा हूं 9.50 रुपए किलो। आज की डेट में, अभी से 10 मिनट पहले तक 9.50 रुपए है, पी०डी०एस० में नहीं, खुले बाजार में भी 9.50 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो फर्क होता है, नारायणसामी जी मेरे से पहले बोले 14.00 रुपए किलो और मैं जब बोल रहा हूं तो 9.50 रुपए किलो पर आटा मिल रहा है। यह फर्क है सरकार के द्वारा लिए गए स्टैप का। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो स्टैप आपने लिया है, निश्चित तौर से उस स्टैप को बरकरार रखिए और जो हमला आपके द्वारा आज पूंजीपतियों पर, कालाबाजारियों पर और जमाखोरों पर हो रहा है, वह निश्चित तौर से प्रशंसनीय है और ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि इस देश के गरीब आदमी को सबसे न्यूनतम, निचले वर्ग के आदमी को अनाज सस्ती दर पर मिले।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मल्होत्रा साहब बोल रहे थे कि 12.00 रुपए किलो आलू और फूल गोभी मिल रही है। यह दिल्ली में जरूर मिल रही होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन सिर्फ दिल्ली का नहीं है, यह सारे देश का सदन है और हम लोग गांव में रहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि गांव में आलू को आज 3.00 रुपए किलो लेने वाला कोई नहीं है और आज हमारे यहां गोभी 4.00 रुपए किलो मिल रहा है। वहां टोकरी में लोग ले—लेकर बेचते हैं 4.00 रुपए किलो, जितनी गोभी खरीदनी हो, खरीद लो। तो यह गांव का रेट, आपने बताया था दिल्ली का रेट और गांव के तथा दिल्ली के रेट में फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल दिल्ली के रेट से सरकार को न तौलिए, अगर सरकार को देखना हो तो गांव के रेट पर भी सरकार को देखिए कि गांव में किस दर पर सामान मुहैया हो रहा है। इसी के साथ-साथ उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किन-किन स्टेट्स में यह ज्यादा हो रहा है, कहां-कहां ये समस्याएं ज्यादा हैं? क्या केवल उन्हीं स्टेट्स में तो ये समस्याएं ज्यादा नहीं हैं, जिनमें हमारी समर्थक सरकारें नहीं हैं? वहां यह इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमारी सरकार, संयुक्त मोर्चे की सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार बदनाम की जा सके। इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को भी और माननीय मंत्री जी को भी और उनसे आश्वसन चाहते हैं कि जो साजिश 1980 में रची गई थी, उस साजिस को आप दोबारा नहीं रचने देंगे, उस साजिश को आप नाकाम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir. I do not think there is any use blaming this Government or that Government for the rise in prices. Administration does matter, but not in all cases. The main thing is the kind of economy you drive. That is the main question as I understand it. This Government is frank to admit that so far as economy is concerned, it is following the policies of the previous Government. So far as I understand, the main party which is in the Opposition also accepts the policies adopted by the previous Government. There was price rise in the post-reform period. We have been assured that liberalisation will give us a price-rise-less economy and an inflation-free economy. I have the current bulletin of the Reserve Bank of India. It says, between 1980 and 1990, the rise in the consumer price index was 9.1 per cent.

During 1991-94, it was 10.4 per cent. During 1994-95, it was 10.3 per cent. In 1995-96, it is 10 per cent. It is clear that price rise has accelerated during the post-reform period, after liberalisation. The current figures—point to point fixation—of April to mid-November 1996 show the rise in the CPI as 7.8 per cent as against 8.2 per cent in the previous year. So far as the CPI is concerned, the rise is less than that of the previous year. But I am not concerned with the CPI. I am concerned about inflation. Inflation should not go up. But inflation is going up. It has gone up to 6.9 per cent from 4.2 per cent in July. I am mere concerned about the rise in prices of essential commodities. The rise in wholesale prices of foodgrains is 12.3 per cent. If you convert it to annual average of CPI it is 16 per cent. Mr. Vice-Chairman, Sir, whenever we raise this issue of price rise in this august House, we are told that prices are coming down. But the fact is that prices of foodgrains are rising. The rise in prices and the fall in the real wages of workers is creating havoc. So far as price rise in the recent period is concerned, I have the Government figures. CMIE figure shows between March, 96—Sept. 1996, it is in the case of rice, the price rise is 8.11 per cent; atta—19.3 per cent; moong dal—36.18 per cent; arhar dal—22.73 per cent; tea—23.13 per cent; chillies—22.89 per cent; cummin seeds—42.63 per cent. All these are essential commodities. Between March and September, the price has risen by 42 per cent. But this does not mean that prices have risen during the regime of this Government. I have the figures given by the Ministry of Civil Supplies. The rise in prices of essential commodities between March 95 and March 96 is more than 36 per cent. In the case of arhar dal alone, it is 42 per cent. The price of salt had risen by 110 per cent in the previous year.

3.00 p.m.

Therefore, the trend is set during the previous Government. In the current period it is getting accelerated and it is the result of the economy the Government is following and besides that, I understand the Government should have taken up, stringent measure beforehand. If it does not take such steps to reform the previous system and other systems, it will do havoc in the current period, in the coming period. But the fact is that, three michiefs are committed by the previous Government also. That has to be understood. In July, 1995, the stock of the foodgrains was 35 million tonnes. It has dwindled to 22 million tonnes by March, 96 during the six month period. That export of two million tonnes of wheat outside the country...(*Interruptions*)...It is also sold at subsidised rate, not at international market rate and the stock has dwindled and they have not procured also. They have withheld the decision on the matter of petrol and other things. As a result of squeeze of credit, squeeze of liquidity, money supply has gone down to an extent. An artificial price level was maintained and now money supply has also increased in the recent period. For electoral purposes, two or three decisions of the previous Government are responsible for the current level of hike. Sir, now the thing is that, if you quite remember, the crisis of 1965 emanated from the heavy rise in the prices foodgrains. The crisis of 1975 emanated from the heavy rise of the foodgrains. Therefore, the current rise of 16 per cent level is...(*Interruptions*)...This is my maiden speech on economics.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): However old a member may be in this House, since it is his maiden speech on economics, he should be protected.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Kindly conclude.

SHRI JIBON ROY: I am concluding in two or three minutes.

Mr. Vice-Chairman, the thing is that, we should put our heads together. We should see how we can come out to their rescue. When the great crisis broke out. I

remember, during 1965 as a young boy, I was working in a factory. From that period, always the rise of prices started from foodgrains. Nobody was looking into that matter. A number of calculation have appeared in the newspapers that the real wages at the lowest level are going down. In this august House is announced a number of times that the real wages are increasing. But according to recent calculations most of the States real wages have gone down at minimum. It has happened in Karnataka, the home-State of our Prime Minister; the real wages have gone down in Maharashtra, the most industrialised State in the country; the real wages has gone down in Delhi, Kanpur. If this is allowed to continue that means people will die like flies. A serious political crisis will be created if the Government does not take not of the situation and also I would like to ask the Government whether or not they will follow the economic policies shared by the previous Government *in toto* or they will make some adjustment and they will give protection to the people who are in the lowest strata of the society. I congratulate the Government of India which is taking a decision to extend the period of PDS system to the people who are below the poverty line at 50% rate and the poverty line is being redrawn taking the consumer price index into consideration and I congratulate the Government for this. It is not the political party nor the Government which is in power or outside, it is the people who are concerned, it is the people should be taken into consideration in dealing with the matter. Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, recently the hon. Minister had made a 9-page statement in this House. Even after that statement, I think the situation of the market has not improved. We have declared ourselves to be a free market economy. I think the traders and the hoarders have teken this statement literally. It is free for all. We do not see any seriousness on the part of this Government to see that the problems of the common man are redressed.

About two years ago, our country had 20 million tonnes of foodgrains surplus. I remember last year when Rashtrapathiji visited Namibia, one of the African countries which he visited—we happened to be in Namibia—he was told that country did not have enough foodgrains. Immediately arrangements were made to supply foodgrains to them free of cost as aid. That was the position of the country about a year ago. The previous Government had also introduced the mid-day meal scheme. One of the reasons for this is that we do not have enough storage facilities and foodgrains were in surplus. I do not blame any Minister or any Government for this. But will it not be proper on the part of our national policy planners to see that there is some control as far as the question of supply of essential goods is concerned, even if we are to be a market economy? Increase in the prices of petroleum products is about 25%. There is deficit in the Budgets of every Government up to the extent of 60%. As a result, the Government is pumping money into the market which will certainly increase the rate of inflation. At the moment, the rate of inflation is 6.8%. Every now and then, we hear news on Doordarshan that such and such corporate house was raided, so and so executives were arrested like criminals. When I say this, I am not holding a brief for these people. We should do it because it is the law of the land. At the same time, we should not intimidate the corporate houses because other people are also involved in this. I am not making any charge. But whoever are involved, whether they be corporate people or the hoarders, black-marketeers, we should arrest them and we should show them on television. I think such an action would send right signals to hoarders and black—marketeers.

Hoarding is done not only by the trading community but sometimes by the

States also. When I say 'States' it is the machinery of the State Governments. Here I make a charge against the FCI. FCI releases the PDS quota to the State Government concerned. But here is a *quid pro que.* Officials of the State Governments are also involved here. They see to it that the State's quota is not released on time. FCI releases the State's PDS quota every fortnight which is supplied to the people through the ration shops. This quota, however, is released by the FCI conveniently on the 13th day of the fortnight. As a result, the poor people have to go to open market to buy their requirements for two weeks. The balance of the quota which is released to the ration shops again goes into the black market. The ration cardholders have to buy their requirements in the open market. It is precisely because FCI does not release the quota every fortnight on time. My query to the Government is: What mechanism does the Government intend to follow? What directives the Governement of India intends to give or has given to the State Governments to see that the balance quota released for the purpose of ration supply through the PDS is accounted for in the next fortnight?

I would further like to say that there is smuggling, both international and inter-State. For example, in my own State, Goa, most of the PDS quota goes across the border to Karnataka State. I have nothing against the people of Karnataka. But the people of my State are denied their ration. Again, Kerosene is being supplied through the PDS at the rate Rs. 2.75 ps. It is heavily subsidised by the Government. At my request—and I am glad the hon. Minister wrote to me—they have mixed a dye, blue dye, in the kerosene being supplied through the PDS. Kerosene is sold in the open market at Rs. 6/- per litre. The PDS kerosene is being sold in the open market which is supposed to be sold in the ration shops. So, there is a need to have a foolproof mechanism in the Indian oil companies or the CBI or the vigilance authorities of the Central Government, not the State Government. I say this because I have already charged that some officials of the State Governments are involved in the hoarding of foodgrains. The officials are involved in hoarding. Unless there is a proper mechanism available with the Central Government, which is the custodian of foodgrain stocks, and which controls the Food Corporation of India and the Oil Corporation of India, I don't think we will be able to control it. Sir, we often read in newspapers and we also debate in the House that edible oils are being smuggled from across the borders. We heard that the Rajasthani satin is going into Pakistan from Gujarat. From the North-East, things are going into Burma and other places. How is this possible? It is only possible by depriving poor people, 40% of the population which is below the poverty line. They are being deprived of by 2% of the total population who are involved in hoarding and black-marketing. Sir, 60% of our economy is in black and it is controlled by 2% of the total population. As a result, 40% people are below the poverty line. So, it is high time we tightened the screws of our system. It is not enough for us to blame the system. We have to blame ourselves. We have to blame the people who are in power. We have to blame the parliamentarians here because they take things very lightly. We allow every Government to go scot-free.

Sir, our Constitution has given equality to every citizen and the Government has taken this really seriously. Every citizen in this country — an Income Tax payee, a Wealth Tax payee, a poor man — has a ration card. I agree with Mr. Narayanasamy when he says as to why the Members of Parliament should have ration cards when they can afford to pay and buy things from the open market. Unless we have a system where the poor can get what is due to them, I don't think the society and posterity will forgive us.

The Minister made a statement that they had to fulfil their commitment on export. We have shortage of foodgrains, including wheat, in this country and the Government blames the previous Government that since there was a commitment, they had to export 4,31,000 tonnes of foodgrains. Sir, there is a saying that in a country people eat what they get and not what they want. You give them what is due to them. You can't keep them hungry. It was a wrong policy to say that they had to export in order to fulfil their commitment. They could have gone to the international market where wheat was cheaper than what our Government pays for procurement. It was a very wrong policy on the part of the Government.

Again I would say that there should be a foolproof system to see to it that there is accountability and foodgrains flow properly from FCI to the State granaries and from the State granaries to the PDS. If we don't have a foolproof system, then we find that the officials get involved in hoarding. Sir, it is not the traders but the Government officials — they may be from the FCI; they may be from the Civil Supplies Departments or it may be the concerned Ministers — who are involved in hoarding. So, it will be proper for the Government to see to it that the Essential Commodities Act and the Consumer Protection Act are brought into force and these people are hauled up. We had done that during the Emergency when hoarders were hauled up and they were exposed on the television. I think that is the only way in which we can control the prices in this country.

Sir, there is one last point regarding LPG. LPG is heavily subsidised by the Government. The Government also gives LPG connections for commercial use, for example, to hotels, etc. But what do we see? For example, in my own State which has a big hotel industry, the LPG supplies meant for domestic consumption are being diverted to the hotels. As a result, these people don't take LPG connections meant for commercial use. In this case also, Sir, it happens with the connivance of the State Government officials and the concerned Ministers. Unless the Indian Oil Co. gets into action and uses the Central Government machinery to see to it that the people get what is due to them, I don't think it will be proper for any Government to remain in office.

With these words, I hope the hon. Minister will react to my suggestions.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this subject. Sir, there are three factors which are responsible for price hike. The first is non-exploitation of agriculture potential which is available in our country. The second is curbing the activities of hoarders and middlemen. The third is monitoring of distribution system. So, these are the three factors which are responsible for price hike. Sir, there is a Department under the Central Government called Department of Wasteland Development. There are large tracts of land in our country which are not being properly exploited. Due to want of sufficient funds crops are not being raised on this land. The agriculturists are not helped during their distress. Our agriculturist is not getting proper returns from agriculture. There are several factors which are responsible for that. Firstly, agricultural labour is not easily available and it is slowly getting extinct. Secondly, there has been an increase in the prices of fertilizers, pesticides and agricultural implements. In fact, these things are not within the reach of an agriculturist. As a result of that, an agriculturist is not able to use it for raising crops. Even if he is able to raise crops, his crops go waste due to natural calamities like floods, drought or some other natural calamities and no proper compensation is given to him. Therefore,

I have suggested so many times that there should be a crop insurance scheme. It would help the agriculturist if his crop is affected by natural calamities by way of compensation. If the crop insurance scheme is implemented properly, it would help the agriculturist a lot. He will not feel the pinch of destruction caused by natural calamities. In case his crops are destroyed and he is not compensated properly, then he will not have sufficient resources to raise the next crop. Hence, the agriculturist is not protected. If proper protection is given to the agriculturist, then he will try to increase agricultural output. Even after raising a crop, he is not getting proper price for it. He is getting the lowest price. There is two-fold or three-fold difference between the price between farmer production price and the price at which it is sold to the consumer. There are middlemen, hoarders, etc., who are involved in blackmarketing. These people hoard everything and then sell these things at exorbitant prices to the consumer. So, this gap in distribution has to be bridged by proper monitoring. Unless it is done, it is not possible to control the price hike. I even charge that both the Central and State Governments have failed in discharging their responsibility of controlling the prices of essential commodities.

Furthermore, Sir, when agriculturists raise a produce, they have no power to determine the price. He has no power to determine the price at which he has to sell.

Lastly, he is at the mercy, at the beck and call of a few agencies which are able to finance him when he is in need. This is the juncture where the Government should come forward to support in terms of finance and other things in time. If these things are not given, and if a proper price is not given, the agriculturist will not be able to produce much. As these things are not made available, most of the agriculturists are converting their valuable agricultural farm-lands into house-sites. Wherever labour problems and other things are there, in most of the lands, agriculturists are not able to raise crops. They simply plan to have coconut-groves or mangroves, just like that. These are some factors that contribute for the insufficient production. Even if they have the production, because of black-marketing and other things, prices are increasing and they are not controlled. It is high time the Central and the State Governments evolved some machinery to see to it that middle-man business is avoided and that agriculturists are protected properly. With these, I conclude, Sir.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, Price rise is not a new phenomenon. I do not want to squarely blame this Government as being solely responsible for this. Two questons arise mainly: Why price rise and what actions you take. Of course, the Government may not agree, but the Government also has to play an important role, the primary role; it is the co-ordination between the Centre and the States. Sir, we know that traders are the main players in the game and they are greedy, profit motive fellows and they have no social responsibility at all. The only controlling force is the Essential Commodities Act to book hoarders and black-marketeers. The question is: Is there a laxity in production? According to the Economic Survey Report 1994-95, the rice production was expected to be 78 million tonnes and the producttion was 81 million tonnes. In 1995-96, expected production was 80 MT and actual was also 80 MT. Expected wheat production was 58 MT and the actual was 65.5 MT. In cereals only there is a downfall. Expected was 36 MT and the actual production was 30 MT. My point is, it clearly shows that there is no reduction in production. Rather, it is increasing. Then, why scarcity and why price rise? This is the major question to be answered. The Government must look into this. Rice and wheat are the staple food. I have a grievance against the Government. Your procurement is not as expected. The

procurement was 8.1 MT as against 12 MT in the past. In stead of 12 MT, you have gone down to 8.1 MT only. That is the main reason.

You know that PDS needs only about 19.5 MT throughout India. Kerala's case is a different matter altogether, it needs more. Sir, the Government is also an accused in this case. Look at the issue price. When the procurement has gone down, the open market availability was more. Eventhough the availability in the open market was more the traders created a havoc on the Government putting pressure on the Indian economy. Poor Finance Minister answered in this House why inflation goes up! Unfortunately, as Mr. Fernandes put it, nobody is serious about food economy. Food economy plays an important role. It has an important component on the economic system in this country. Unfortunately, we give least importance to this. This is one of the reasons why inflation goes. up. Sir, I do not want to go into its details. But, Sir, I accuse the Government. The Governmnet has committed a mistake. The Central issue price has been increased by 25 per cent. When you raise this price by 25 per cent, naturally traders also increase the prices. Sir, the price of wheat was Rs. 4/- per kg. Now it has been increased to Rs. 5.02. The price of rice was Rs. 6/- per kg. It has now gone up to Rs. 7.43 ...(*Interruptions*)...I am mentioning only the issue prices. Sir, the prices have gone up by 25 per cent. Naturally, reaction of it will also be there in the open market. The Government has to look into it and ensure to what extent they can control the prices through PDS. By the time commodities reach the PDS for which State Governments also pay some money, the prices of these commodities are almost equal to the prices in the open market. Now, the prices in the open market have gone up. I agree, as pointed out by Mr. Malhotra, the previous Government was exporting wheat at the rate of 175 dollars per tonne. But, this is still going on. Now, on the one hand, we are importing, and, on the other hand, we are exporting. The Government should look into this matter thoroughly and see what can be done. Instead of a piecemeal thinking, let us have a total plan to control the prices of commodities.

Now, I would like to mention one or two points with regard to sugar. Sir, the production of sugar is 154 lakh tonnes. It is 20,000 tonnes more than last year. There is no scarcity of sugar. There is no need to increase the price of sugar. Yet the price of sugar is going up. If you look at it in totality, you will find that it is not that production has gone down or that it is not due to drought and floods. It is because something has gone wrong somewhere. You have to look into that aspect and find out where we went wrong or what was wrong with us. Sir, if you look at the figures, the total availability has gone down. This is worrying me. In October it was 1.22 million tonnes. Now it has gone down to 1.17 million tonnes. That is why the price of sugar has gone up.

Another point that I want to mention is with regard to railway wagons. Sir, the railway is also playing a havoc. As far as railway wagons are concerned, the FCI needs more wagons. Though food items are the first priority, we find that in Kerala railway wagons are not available for this purpose at all. Naturally, there is a full-stop and prices continue to go up. Therefore, there should be some interlink and coordination amongst various Ministries. As pointed out by Shri Naryanasamy, there should be some cooperation among the various Ministries so that the prices of essential commodities do not go up.

As far as PDS is concerned, I disagree with some of my friends. Sir, in Kerala ration-card is a statutory thing. The ration card is not required only for ration. I do not know how many MPs go to the ration shops. It is a kind of document. Even if you want to have a passport, you require a ration-card. In Kerala it is a statutory thing and every family has a

ration card there. ...(*Interruptions*)... As far as PDS is concerned, it is a good thing for those people who live below the poverty line. But, at the same time, the PDS has also to be strengthened. My complaint is that the PDS is not strengthened because sufficient supplies are not there. When you increase the issue price, naturally there is increase in prices in the market also.

Sir, I suggest that the PDS system should be strengthened by giving sufficient supplies, particularly of wheat and rice because any delay in the release of stocks will create a problem in the market. There should be adequate availability of wagons for transporting these items and wheat and rice should be the first priority. Thirdly, the Government should invoke the Essential Commodities Act because there is no scarcity of essential items in the country. It is only an artificial scarcity created by the hoarders and blackmarketeers. I also request the hon. Minister to convene a meeting—he held one meeting, I know that—of the State Food Ministers because they are the people who implement the law, they are the people who invoke the law; they are the people who can put these people behind bars. Of course, all this needs a better kind of operation. I do not want that the prices are further increased by arresting some people. It should be done in a tactful way. Sir, I know the traders are bigger than us It is very difficult to deal with these fellows. Sir, everybody agrees that there is price rise, everybody agrees that there is a problem. But, at the same time, we must understand that this is an artificial scarcity created by certain people. Therefore, the Central Government should take steps to deal with this problem in consultation with State Governments. With these words I conclude. Thank you.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह अल्पकालिक चर्चा जो हो रही है आवश्यक वस्तुओं की महंगाई के संबंध में इस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन जो विषय है पूरी तरह से उस विषय पर विचार नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली में गेहूं महंगा हो गया और संसद में हम लोग इस पर गंभीर चिंता प्रकट कर रहे हैं, एक दिन अखबार ने कहा था कि मुम्बई में भी गेहूं महंगा हो गया है। दो शहरों में महंगा ज्यादा हुआ तो मुझे सोचना पड़ा कि इन दोनों शहरों में किसी एक पार्टी की सरकार है ...(व्यवधान)

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: बिहार में? उड़ीसा में? मौतें हो रही हैं।

श्री ईश दत्त यादव: लेकिन हमें इन दो शहरों या दो प्रदेशों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आवश्यक वस्तु केवल गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है। है, लेकिन इसके साथ दवा भी है, इसके साथ कृषि यंत्र भी हैं, इसके साथ खाद भी है, इसके साथ सीमेंट भी है। ये सभी इसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आती हैं। हम इन पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम केवल 20 फीसदी लोगों की आवाज को उठा रहे हैं जिनके पास जबान है, जो शहर में रहते हैं। 20 फीसदी हैं, हम उनकी आवाज को उठा रहे हैं। जो 80 फीसदी गांवों में रहते हैं, जिनके बच्चे बिना रोटी खाए सो जाते हैं जिनके पास जबान नहीं है, हम उनकी आवाज को नहीं उठा रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): वैसे भी सिर्फ चार मिनट समय है आपका।

श्री ईश दत्त यादव: क्योंकि समय सीमित है और हमारे खाद्य मंत्री जी श्री देवेन्द्र यादव जी के अधिकार और विभाग भी सीमित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से, भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें क्योंकि दो जगह उत्पादन होता है। एक जगह जहां धुआं उठता है जिसका नाम कारखाना है। मशीन से चलता है। एक जगह जहां धूल उड़ती है। उसका नाम खेत है और इसमें काम करने वाले किसान और गरीब मजदूर हैं जो धूल में काम करते हैं, जो धुएं में काम करते हैं। इन गरीब और मजदूरों पर महंगाई की मार कितनी पड़ी है इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में 10 रुपए किलो आटा हो गया है। मैं भी चिंतित हूं। दिल्ली के लोगों को सस्ता गेहूं मिलना चाहिए। इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो गरीब है वह महंगी दवा के अभाव में मर जाता है। किसान के खेत में खाद न पड़ने की वजह से उसके खेत का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। हमारी साथी और हमारे जिले के मोहम्मद मसूद खान साहब पीछे बैठे हैं। हम लोग एक जगह के रहने वाले हैं। कह रहे हैं कि खाद हमारे

जिले में नहीं मिल रही है। कल लौटकर आए थे। खाद जो किसान को मिलनी चाहिए वह गायब हो गयी है। अगर खाद किसान के खेत में नहीं पड़ेगी तो आपका गेहूं 20 रुपए किलो दिल्ली में बिक सकता है। इस पर क्यों नहीं चिंता प्रकट करते हैं। इस पर हमें भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। मैं कल रात टी०वी० पर देख रहा था कि चार प्वाइंट कुछ डिग्री सेल्सियस दिल्ली का टेम्परेचर हो गया है। लखनऊ का भी इसी के आस पास है और गांवों का भी इसी के आस पास है। कपड़े के अभाव में जो ठिठुर कर मर रहा है, कपड़ा महंगा होने के कारण, उन महंगाई पर भी सदन को गंभीरता से विचार करना है। सारी जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं जिनके बिना आदमी का जीवन दूभर हो जाता है...(**समय की घंटी**)—मैं अब समाप्त करूंगा—जिनके न रहने की वजह से आदमी मर जाता है...।

आज इसका कृत्रिम अभाव इस देश के अंदर है। देश के अंदर गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन कृत्रिम अभाव है। होर्डिंग हो रही है। सरकार को और खाद्य मंत्री जी को चाहिए कि जो होर्डिंग हो रही है उस पर वह कंट्रोल करें। जो आपकी वितरण प्रणाली है वह ठीक नहीं है। इस गलत वितरण प्रणाली पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करूंगा। संभव है मूल्य निर्धारण करने वाली आपकी कोई समिति होगी उसको इन बातों पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिद्धान्त है कि दो फसलों के बीच में दस प्रतिशत से अधिक महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। अगर गेहूं की फसल पैदा होते समय सौ रुपया क्विंटल है तो आने वाली फसल तक वह 110 रुपये क्विंटल तक बिकना नहीं चाहिए। कारखानें के माल का एक रुपये अगर लागत मूल्य है तो देश के किसी भी कोने में डेढ़ रुपये से ज्यादा नहीं बिकना चाहिए। यह आपकी सरकार को करना पड़ेगा और तब जाकर आप मूल्यों पर नियन्त्रण कर सकते हैं।

मान्यवर, मेरे एक-दो और सुझाव हैं। यह केवल गेहूं, चावल, दाल की समस्या नहीं है, इससे ज्यादा समस्या उत्पादन की है। मुझे भय है, शंका है कि अगर सरकार की यही नीति रही तो खेत का उत्पादन कम होने वाला है क्योंकि खेती अब घाटे का बिज़नैस मानी जा रही है किसान जो खेत में पैदावार करता है आप उसका समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे हैं। साढे चार सौ रुपये क्विंटल में गेहूं की पैदावार हो रही है। मैं मोटे तौर पर बतला रहा हूं। आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के लोगों ने कहा कि मोटे तौर पर साढे चार सौ रुपया क्विंटल गेहूं का उत्पादन मूल्य है और आप उसको तीन सौ, सवा तीन सौ रुपये के हिसाब से देंगे। इससे किसान हतोत्साहित हो रहा है। देश में उत्पादन घटने वाला है डा० नौनिहाल सिंह जी बड़ी विद्वान हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, वह मेरी बात से सहमत होंगे। शुगरकेन का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन कम होने जा रहा है। मैं यह व्यथा इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं क्योंकि गांव में रहता हूं और छोटा-मोटा किसान हूं। आपके मिल का जो गन्ना गया उसका आप भुगतान नहीं कर रहे हैं। गरीब की जब जरूरत है, दवा के लिए, कपड़े के लिए, खाद के लिए उसको पैसा नहीं मिल रहा है। वह गन्ने का उत्पादन क्यों करेगा? देश के अन्दर चीनी घटने वाली है। आज अखबार में पढ़ रहा था और मल्होत्रा जी भी कह रहे थे कि 20 लाख टन आप गेहूं आयात करने वाले हैं। यह हमारे लिए शर्म और लज्जा की बात होनी चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारी भूमि सोना उगलने वाली भूमि है, उपजाऊ भूमि है और हम गेहूं आयात करने की बात सोच रहे हैं?

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ खाद्य मंत्री जी से कहता हूं, इनका विभाग तो सीमित है, लेकिन भारत सरकार और देश के प्रधान मंत्री जब तक देश की अर्थ व्यवस्था पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे, देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई और बढ़ेगी। 15 साल पहले की बात देख लीजिए। कारखानें में बना हुआ सामान 50 गुना, 20 गुना/ 30 गुना बढ़ा या नहीं, दवा का दाम सौ गुना बढ़ा या नहीं? गरीब दवा के अभाव में मर रहा है। अस्पतालों में दवा नहीं है। गरीब दवा खरीद नहीं सकता। इस पर भी भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तभी देश की अर्थ व्यवस्था सुधरेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि महंगाई पर नियन्त्रण करने का वह हर संभव प्रयास करें। मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधाकृष्ण (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जीवन की आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं इसमें कोई विवाद नहीं है। सब से ज्यादा आवश्यक वस्तु रोटी होती है। रोटी के लिए आटा चाहिए और आटा गेहूं से बनता है। गेहूं के दाम बढ़े हैं। गेहूं के दाम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बढ़े हैं, बम्बई में ही नहीं बढ़े हैं, गेहूं के दाम

उड़ीसा में भी बढ़े हैं जहां भूख से मौतें हो रही हैं, गेहूं के दाम मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड इलाके में भी बढ़े हैं, जहां तीन-तीन बार दुकानें लूटी गई। भूखे लोगों ने इसलिए दुकानें लूटी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं उपलब्ध नहीं था।

मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां कि गेहूं सब से ज्यादा पैदा होता है, वहां भूखे लोगों ने मजबूर होकर गेहूं की दुकानें लूट लीं। जहां एक ओर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लोग भूख से मर रहे थे और गेहूं की दुकानें लुट रही थीं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री 15 हजार लोगों के बीच में बैठकर ऐश कर रहे थे, भोज कर रहे थे और अपने शासनकाल के तीन वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ मना रहे थे। मान्यवर, यह शासकीय तंत्र का फेलुअर है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का फेलुअर है। दरअसल गेहूं की उतनी कमी नहीं है जितना कि व्यवस्था का अभाव है क्योंकि आज से सवा साल पहले गोदामों में गेहूं रखने के लिए जगह नहीं थी। इतना गेहूं सरकार के पास था। भारतीय खाद्य निगम खुले मैदान में गेहूं रखता था और गेहूं सड़ रहा था। लेकिन आज सवा साल बाद स्थिति यह हो गयी कि आप कह रहे हैं कि हमारे गेहूं के गोदाम खाली हैं। मान्यवर, सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि लोगों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो इस बात में लगी हुई है कि यह तो दिल्ली सरकार की गलती है, हमारी गलती नहीं है। मान्यवर, मंत्री जी ने यहां पर जवाब दिया था कि दिल्ली के 6 गोदामों को मिलाकर सारे-का-सारा स्टॉक 53 हजार क्विंटल है जबकि उन की हर महीने की आवश्यकता 60 हजार क्विंटल की है एक महीने की आवश्यकता का आप के पास गेहूं नहीं है और आप कह रहे हो कि गेहूं हम दिल्ली सरकार को खूब दे रहे हैं और फिर उन को कोस रहे हो। तो इस तरह की बातें करने में और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने में लगे रहेंगे तो आप व्यवस्था सुधार नहीं सकते हैं।

महोदय, हिन्दुस्तान में एक बादशाह हुआ था जिस का नाम मोहम्मद तुगलक था। उसने लोगों के कहने पर अपनी राजधानी बदल दी और वहां पहुंचा तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर राजधानी वापिस यहीं ले आया। यह सरकार भी मोहम्मद तुगलक से किसी प्रकार कम नहीं है। अभी 4-6 महीने पहले इस ने गेहूं का निर्यात किया है, आटे का निर्यात किया है। जब सरकार को मालूम था कि गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, गेहूं की खरीद कम हुई है तो क्या आवश्यकता थी गेहूं का निर्यात करने की? अब जब गेहूं की फसल दोबारा आने वाली है तब यह सरकार 20 लाख टन गेहूं का आयात करने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह गेहूं मार्च महीने से पहले आने वाला है? अगर मार्च के महीने से पहले नहीं आने वाला है, अगर जनवरी में नहीं आने वाला है तो गेहूं को आयात करने की आवश्यकता क्या है? महोदय, मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में भरपूर गेहूं की फसल आती है। वह फरवरी के अंत में ही आनी शुरू हो जाती है। उस वक्त तो किसानों का जो गेहूं बाजार में आने वाला है, उस के भी दाम कम हो जायेंगे। तो अगर आप यह कर रहे हैं तो उस का आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है।

माननीय मंत्री जी मैं आप को यह भी बताना चाहता हूं कि गेहूं के ही दाम नहीं बढ़े हैं और भी कई चीजों की, जिन की आम तौर पर आवश्यकता होती है, उन सब चीजों के दाम बढ़े हैं और ये मेरे आंकड़े नहीं है, आप के ही यह आंकड़े है। इन के थोक मूल्य मार्च, 95 से मार्च 96 तक कितने बढ़े हैं, यह मैं आप को बता रहा हूं। यह दाम आज तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं उन में से थोड़े से आंकड़े आप के सामने रखना चाहता हूं—नमक के दाम 110.6 परसेंट बढ़े हैं। प्याज जिस के लिए कभी कांग्रेस सरकार ने बहुत हल्ला मचाया था और सरकार बदलने की कोशिश की थी, उस के दाम 58.6 परसेंट बढ़े हैं। यह थोक मूल्य की कीमतें हैं जोकि बढ़ी हैं। अरहर 36.7 परसेंट, मूंग 26.7 परसेंट, मसूर के 32.8, आलू 36.5, मिर्ची 34.5, चाय 25.5 और खादी के कपड़े के 25.6, साबुन के 16.6 और सीमेंट के 11.7 परसेंट बढ़े हैं। यह जो कीमतें बढ़ी हैं उन का थोक मूल्य सूचकांक है मार्च, 96 की कीमतों के ऊपर जबकि आज दिसम्बर है और इन कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है जब कि ये उस वक्त के दाम हैं जब मार्च में फसल आती है और आज तो हालत बहुत ही खराब है। महोदय, ये दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिल्कुल फेल हो गयी है। मध्य प्रदेश में सागर जिले की रेहली में दुकानें लूटी गयीं, चंदेरी जिला गुना में दुकानें लूटी गयीं और टीकमगढ़ के जिला मुख्यालय में दुकानें लूटी गयी क्योंकि जिन लोगों के पास खाने को दाना नहीं है, उन के पास इस के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। सस्ते बाजारों में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में अगर गेहूं उपलब्ध नहीं होगा तो इस के सिवाय कोई रास्ता नहीं

है कि जहां मिल रहा है वहां से उठाकर अपनी पूर्ति करें। उन के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए उन को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मान्यवर, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं जाता कहां है? यह गेहूं जाता है कालाबाजार में। यह गेहूं जाता है कैरन कुक की दुकान पर और यह गेहूं जाता है तस्करी में। महोदय, गेहूं की बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है। कलकत्ता से गेहूं बांग्लादेश की तरफ चला जाता है और यह गेहूं इस तरह हमारे देश से बाहर निकल जाता है।

उसको रोकने की कोई चिंता नहीं है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुधारने की कोई चिंता सरकार को नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आज सरकार यह निर्णय लेती है कि 20 लाख टन गेहूं का आयात करेंगे। तो सरकार को यह स्पष्ट बताना चाहिये कि यह गेहूं किस भाव से खरीदा जा रहा है, कहां से खरीदा जा रहा है? और, क्या यह गेहूं हिन्दुस्तान के सुदूर गांव तक पहुंच सकेगा? अगर आपके पास फरवरी तक यह गेहूं पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, जनवरी तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है तो आयात करने का कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो फिर किसानों के ऊपर ही मार पड़ेगी क्योंकि किसान का जो माल बाजार में आने वाला है वह सस्ता बिकेगा। मुझे मालूम है, पिछली बार जब किसानों की फसल गेहूं की आई बाजार में तो सरकार की एजेंसियां फेल हो गई थी उस गेहूं को खरीदने में, बल्कि जानबूझकर उनको नजरअंदाज किया गया। आपकी यह जो 10 लाख टन गेहूं की वसूली कम हुई है वह इसलिए नहीं हुई कि बेचने वाले मौजूद नहीं थे। बेचने वाले तो मौजूद थे, लेकिन सरकार ने गेहूं खरीदने में कोताही की। माल पड़ा हुआ था मंडियों में और सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। इसी कारण किसान को समर्थन मूल्य के नीचे मध्य प्रदेश की कई मंडियों में अपना गेहूं बेचना पड़ा। उस वक्त सरकार गेहूं खरीदने में फेल रही।

महोदय, जब जरूरत होती है तो सरकार गेहूं खरीदती नहीं। उस वक्त किसान लुटता है और आज खाने वाला लुट रहा है। आज लोगों के पास मजदूरी नहीं है, उनको काम नहीं मिल रहा और इसीलिये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ एरिये में भूख से मौतें हो रही हैं। वहां लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है और इसके कारण वहां यह हालत खराब हो रही है।

अंत में, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो इन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए चिंतापूर्वक सरकार कोई व्यवस्था करे, कोई ऐसा रास्ता निकाले, जिससे कि किसानों को भी नुकसान न हो और उपभोक्ताओं को भी राहत मिले। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): श्री जलालुदीन अंसारी। आपकी पार्टी के लिए दो मिनट का समय है, लेकिन आप बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर के संक्षेप में बोलें।

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे साथियों ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर अपनी चिंता जताई है, मैं भी उस पर अपनी चिंता जताने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह चिंता देश की गरीब जनता के प्रति है क्योंकि गेहूं, आटा, चावल, कैरोसिन तेल, चीनी, दाल आदि, जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी हैं उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और सरकार के आश्वासन के बावजूद भी उनकी बढ़ती कीमतों को रोकने में वह विफल रही है, चाहे वह राज्य सरकारें हों या हमारी दिल्ली की सरकार हो। अभी इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं क्योंकि सत्र चल रहा है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी निर्भर करता है कि आवश्यक चीजों की कीमतें स्थिर रहेंगी या बढ़ेंगी।

महोदय, दो राज्यों का उदाहरण तो कम से कम हमारे सामने है, जहां पर पी० डी० एस० लागू है, जन वितरण प्रणाली लागू है केरल और बंगाल में। आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी तो जरूर है कि नियमित रूप से निश्चित तौर पर चावल, गेहूं, चीनी आदि चीजें वहां जन वितरण प्रणाली की दुकानों से जनता को मिल जाती हैं। अभी हमारे राधवजी बोल रहे थे कि गेहूं बंगाल होते हुए बंगलादेश को चला जाता है। आप दिल्ली का भी बता देते कि दिल्ली का गेहूं कहां चला जाता है? मैं यह कहना चाहता हूं कि हर सवाल पर दल की बात आप मत किया कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं कम्यूनिस्ट हूं और रहूंगा, आप भी बी० जे० पी० के हैं और रहेंगे, यह कांग्रेस के हैं और रहेंगे, यह समाजवादी हैं और रहेंगे, यह जनता दल के हैं और रहेंगे, लेकिन जो आवश्यक चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर तो कोई एक राय हम बनाएंगे? चाहे सरकार दिल्ली में आपकी हो, महाराष्ट्र में, राजस्थान में आपकी हो, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हो या दूसरे राज्यों में हो, चाहे कहीं जनता दल की सरकार हो या कम्युनिस्टों की सरकार हो वामपक्ष की, लेकिन इस महंगाई को रोकने के लिए कोई कारगर कदम आप उठाना चाहेंगे या नहीं उठाना चाहेंगे।

तो मेरा कहना है, आपसे भी अपील है कि दलीय दीवारों को हमेशा लाकर खड़ा मत कीजिए और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, यह मेरा निवेदन होगा तमाम दलों के भाइयों से। प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कैसे रोकी जाएं और इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में क्या कोई कोआर्डिनेशन, कोई समन्वय होगा? कुछ राज्य सरकारों ने, मैं जानता हूं नाम लूंगा तो फिर बखेड़ा खड़ा होगा, ऐसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट को खत्म कर दिया, वहां लागू नहीं किया। मेरे ही बिहार राज्य ने यह किया, लेकिन अब सुना है कि खाद्यान्न की कमी होने लगी तो फिर लागू करने का ऐलान हुआ है। तो अगर इस ऐसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट को आप कड़ाई के साथ लागू नहीं करेंगे तो यह जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोग चीजों का कृत्रिम अभाव पैदा करके चीजों की कीमतें बढ़ाएंगे। यह समय-समय पर अपने देश में वर्षों से होता चला आ रहा है। क्या यह सच्चाई से हम और आप इन्कार कर सकते हैं? कई बार तो हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक डि-होल्डिंग अभियान चलाया, सर फुड़वाए, लाठी खाई जमाखोरों की दुकानों पर और हमने गोदामों से उनके अनाज को निकलवाया और कहीं-कहीं तो पुलिस ने भी हम पर लाठी चलाई है और वह मूक-दर्शक बनी रहती है, यह हमारा पिछले दिनों का तजुर्बा है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने खाद्य मंत्री और केन्द्र सरकार से कि कोआर्डिनेशनल सैल बनाएं। दिल्ली में हमने पढ़ा भी है कि दो-चार व्यापारी पकड़े भी गए हैं। दो-चार पकड़े गए तो उससे क्या हुआ? क्या चीजों की कीमतें घटीं? क्या आटा, गेहूं, आवश्यक सामग्री कम दाम पर मुहैया हो रही है? नहीं हो रही है। तो मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक मोनिटरिंग सैल स्थापित करें। राज्यों में भी एक मोनिटरिंग सैल हो और राज्य और केन्द्र का भी एक सैल हो और आपस में समन्वय करके इन ज़माखोरों के खिलाफ, कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से निबटा जाए ताकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने वालों को अवसर नहीं मिले। क्या इसके लिए कोई मेकेनिज्म केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करना चाहती है? जमाखोरों और चोर बाजारियों के खिलाफ अगर आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाएगी। आज देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसके लिए आर्थिक नीति जवाबदेह है? कितने दिन तक आप पैबंद लगाकर काम को चलाएंगे? बहुत बहस हो चुकी है, हो क्या रहा है? सारी दुनिया में और अपने देश में क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चीजों की सीमतें बढ़ती चली जा रही है। मुद्रास्फीति बढ़ती चली जा रही है और जब आप घाटे का बजट पेश करेंगे तो मुद्रास्फीति और महंगाई और बढ़ जाएगी। उस घाटे के बजट का क्या परिणाम होता है? मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के मायने है चीजों की कीमत का बढ़ना। इसको आप रोक सकते हैं क्या? यह तो साधारण अर्थशास्त्र कहता है कि घाटे के बजट का मतलब मुद्रास्फीति और महंगाई का बढ़ना है। इसको कौन से अर्थशास्त्र से आप काटना चाहते हैं? तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस उछाल को रोकने के लिए आप मोनिटरिंग सैल बनाएं केन्द्र और राज्य सरकारों में, चाहे किसी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, और कोआर्डिनेट करके, मोनिटरिंग सैल के जरिए जमाखोरों के खिलाफ, काला धंधा करने वालों के खिलाफ और बनावटी कमी पैदा करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करें। उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने को तैयार है कि नहीं? अगर तैयार है तो इसमें सुधार होगा और अगर नहीं तैयार है तो निश्चित जानिए कि इसमें आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। पिछले दिनों का तजुर्बा हम लोगों को है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि हम अनाज का विदेशों में निर्यात करेंगे और अभी हमने पढ़ा, आज तक पिछली सरकार भी और यह सरकार भी कहती रही है कि हमारे पास अन्न का पर्याप्त भंडार है, एफ०सी०आई० के गोदानों में बफर स्टॉक है, लेकिन अब क्या हो गया कि 20 लाख टन आप आयात करने वाले है,....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): समाप्त कीजिए।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: मैं समाप्त कर रहा हूं। आज क्या हो गया कि आप 20 लाख टन आयात करने वाले हैं, विदेशों से मांगाने वाले है? तो साफ-साफ बताइए कि जब है ही नहीं तो आप कहते है विदेश को देंगे, कहां से देंगे? कमी आ गई अचानाक तो विदेश से लाएंगे, इसके क्या माने है? आप स्पष्ट तौर पर इस देश की जनता को बताइए, सदन को बताइए कि आखिर स्थिति क्या है। हम अभी तक कहते हैं कि बफर स्टॉक है, हम खिलाने में सक्षम है। तो कहां खिला रहे है? लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। कहां खिला रहे हैं? परचेजिंग पावर घट गई है, क्रय शक्ति घाट गई है। पैसा लेकर ढूंढ रहे है लेकिन अधिक कीमत पर भी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति को खत्म किया जाए और मेरा सुझाव

है कि जमाखोरों और कालाबाजरियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें और उसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग लें। जब तक आप इस पर रोक नहीं लगाएंगे, यह काम नहीं होगा। इसलिए आप इस बात पर विचार कीजिए कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं? राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति को रोका जा सकता है या नहीं?

इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। जब तक आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक यह काम नहीं होगा। हम लोगों की एक बहुत पुरानी मांग थी कि 14 आवश्यक वस्तुएं पी०डी०एस० के माध्यम से जनता को दी जाएं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये जरूरी वस्तुएं आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, सरकारी दुकानों के जरिए अगर मुहैया कराएंगे तो निश्चित तौर पर चोरबाजारियों और जमाखोरों को कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि पी०डी०एस० को आप मजबूत कीजिए और इन 14 आवश्यक वस्तुओं को इसके माध्यम से आम जनता को मुहैया कराइए।

महोदय, अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग है, उनको हम पी०डी०एस० के माध्यम से चीजें मुहैया करायेंगे। हम लोगों ने इसका स्वागत किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह काम आप कब तक करेंगे? मैं खाद्य मंत्री जी से और सरकार से मांग करूंगा कि इस पर आप विचार कीजिए और पी०डी०एस० को मजबूत बनाइए। अगर आप सचमुच में गरीब का भला करना चाहते हैं तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ती कीमत पर ये चीजें उपलब्ध कराइए। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो बढ़ोत्तरी हो रही है, इसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाही की जाए।

†डा० सैयद जलालुद्दीन अंसारी "बेहार": आप सभापति महोदय - जो मेरे साथियों ने आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर अपनी चिंता जताई है - मैं भी इस पर अपनी चिंता जताने के लिए खड़ा हुआ हूं -

†[ ] Transliteration in Arabic Script

یہ چنتا دیش کی غریب جنتا سے پوری ہے - کیونکہ گیہوں - آٹا - چاول - کیروسین تیل - چینی - دال وغیرہ جو اسکے جیوت رہنے کیلئے ضروری ہیں - انکی قیمتیں بڑھتی چلی جارہی ہیں - اور سرکار کے آشوا سنوں کے باوجود بھی انکی بڑھتی قیمتوں کو روکنے میں وہ ناکام رہی ہے - چاہے وہ راجیہ سرکاریں ہوں - یا ہماری مرکزی سرکار ہو - ابھی اس وقت ہم لوگ دلّی میں ہیں - کیونکہ سنتر چلا رہا ہے - یہ سرکاری آنکڑے بتاتے ہیں پر میں نرنر کرتا ہے کہ آوشیک چیزوں کی قیمتیں اسطرح رہینگی یا بڑھینگی -

مہودے - دور دراجیوں کا تو ادھر تو کم سے کم ہمارے سامنے ہے - جہاں پر پی - ڈی - ایس - لاگو ہے - جن وترن پرنالی لاگو ہے کیرل اور بنگال میں - آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی نہیں ہے - لیکن اچھی تو ضرور ہے کہ نیمت روپ سے نشچت طور پر چاول - گیہوں - چینی وغیرہ چیزیں وہاں جن وترن پرنالی کی دوکانوں سے جنتا کو مل جاتی ہیں - ابھی ہمارے راگھو جی بول رہے تھے کہ گیہوں بنگال ہوتے ہوئے بنگلہ دیش چلا جاتا ہے - آپ دلّی کا بھی بتا دیتے کہ دلّی کا گیہوں کہاں چلا جاتا ہے - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سوال پر دل کی بات آپ مت لیا کیجئے

نے یہ کیا۔ لیکن اب یہ سنا ہے کہ تہادون کی
کمی ہونے لگی تو پھر لاگو کرنے کا اعلان ہوا ہے۔
تو اگر اس ایسینشیل کامودیٹیز ایکٹ کو آپ
کڑائی کے ساتھ لاگو نہیں کریں گے تو جمع خوری
اور کالا بازاری کرنے والے لوگ چیزوں کا
کرتم اصناعی پیدا کرکے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں گے
یہ سب سے پرانے دیش میں ورشوں سے ہوتا
چلا آرہا ہے۔ کیا اس سچائی سے ہم اور آپ
انکار کرسکتے ہیں۔ کئی بار تو ہم لوگوں نے
کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے ایک دی ہولڈنگ
ابھیان چلایا یا سر بھی ہوئے۔ لاٹھی کھائی
جمع خوروں کی دوکانوں پر اور ہم نے گوداموں
سے رکے ہوئے مال کو نکلوایا اور بھی کہیں تو پولیس
نے بھی ہم پر لاٹھی چلائی ہے اور دوں موکے دشک
بھی رہتی ہے۔ یہ ہمارا پچھلے دنوں کا تجربہ ہے تو
میں آپکا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں
نویدن کرنا چاہتا ہوں اپنے مکادیہ منتری
اور یکندریہ سرکار سے کہ کوآرڈینیشن سیل
بنائیں۔ ستی میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ دو چار
دیا باری پکڑے بھی گئے ہیں۔ دو چار پکڑے
گئے تو اس سے کیا ہوا۔ کیا چیزوں کی قیمتیں
گھٹیں۔ کیا آٹا گیہوں۔ آوشیک سامگری
کم دام پر مہیا ہو رہی ہے۔ نہیں ہو رہی ہے۔ تو
میرا سجھاؤ ہے کہ راجیہ سرکار اور یکندریہ
سرکار ایک مانیٹرنگ سیل قائم کریں۔
یہی میرا آپ سے نویدن ہے۔ میں کمیونسٹ
ہوں اور رہوں گا آپ بھی بی۔ جے۔ پی کے
ہیں اور رہیں گے۔ یہ کانگریس کے ہیں اور
رہیں گے۔ یہ سماجوادی ہیں اور رہیں گے۔ یہ
جنتادل کے ہیں اور رہیں گے۔ لیکن جو آوشیک
چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس پر
تو کوئی ایک رائے ہم بنائیں گے۔ چاہے سرکار
دلی میں آپکی ہو۔ مہاراشٹر میں۔ راجستھان
میں۔ آپکی ہو۔ کانگریس کی مدھیہ پردیش
میں ہو یا دوسرے راجیوں میں ہو چاہے
بہیں جنتادل کی سرکار ہو یا کمیونسٹوں کی
سرکار ہو وام پکش کی۔ لیکن اس مہنگائی
کو روکنے کیلئے کوئی کارگر قدم آپ اٹھانا
چاہیں گے یا نہیں اٹھانا چاہیں گے۔ تو میرا
کہنا ہے۔ آپ سے بھی اپیل ہے کہ دیہ
دیہاروں کو ہمیشہ لاگو کرکے رکھا جائے۔
اور جنتا کے جیون کے ساتھ کھلواڑ مت کیجئے۔
یہ میرا نویدن ہے کہ تمام دلوں کے بھائیوں
سے۔ پرشن یہ ہے کہ آوشیک وستوؤں کی
قیمتیں کیسے روکی جائیں۔ اور اس کے لئے راجیہ
سرکار اور یکندر سرکار میں کیا کوئی کوآرڈینیشن
کی سمجھوتہ ہوگا۔ کچھ راجیہ سرکاروں نے۔
میں جانتا ہوں نام لوں گا تو پھر بکھیڑا کھڑا
ہوگا۔ ایسینشیل کامودیٹیز ایکٹ کو ختم
کر دیا۔ وہاں لاگو نہیں کیا میرے ہی پیارے راجیہ

سادھارن اور تھشا ستر کہتا ہے۔ بجٹ کے بجٹ کا مطلب مدرا اسفیتی اور مہنگائی کا بڑھنا ہے اسلئے کون سے اور تھ شاستر سے آپ کا شاچاہتے ہیں تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اس اچھال کو روکنے کیلئے آپ مانیٹرنگ سیل بنائیں۔ کیبنٹ اور راجیہ سرکاروں میں چاہے کسی راجیہ میں کسی بھی دل کی سرکار ہو۔ اور کوآرڈینیٹ کرکے مانیٹرنگ سیل کے ذریعے جمع خوروں کے خلاف۔ کالا دھندہ کرنے والوں کے خلاف اور بناوٹی کمی کرنے والوں کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ ان کے خلاف آپ کارروائی کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں۔ اگر تیار ہیں تو اس میں سدھار ہوگا۔ اور اگر نہیں تیار ہیں تو نشچت جانیئے کہ اسمیں آپ کنٹرول نہیں کر پائینگے۔ پچھلے دنوں کا تجربہ ہم لوگوں کو ہے۔

اب سبھاد دھیکشی مہودے۔ ایک طرف تو ہماری سرکار کہتی ہے کہ ہم اناج کو ودیشوں میں نریات کرینگے۔ اور ابھی بھنے بڑھا۔ آج تک پچھلی سرکار بھی اور یہ سرکار بھی کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا کا بیر پاپت بھنڈار ہے۔ ایف۔ سی۔ آئی کے گوداموں میں وافر اسٹاک ہے۔ لیکن جب راجیوں میں بھی ایک مانیٹرنگ سیل ہو اور راجیہ اور کیندر کا بھی ایک سیل ہو اور آپس میں سمنوے کرکے ان جمع خوروں کے خلاف۔ کالا بازاریوں کے خلاف سختی سے نپٹا جائے تاکہ آویشیک وستوں کی قیمتیں بڑھانے والوں کو اور موقع نہیں ملے۔ کیا اسکے لئے کوئی میکینزم کیندر سرکار اور راجیہ سرکار ملکر کرنا چاہتی ہیں۔ جمع خوروں اور چور بازاریوں کے خلاف اگر آپ سخت کارروائی نہیں کرینگے تو دیش کی آرتھک استھتی بگڑتی جائیگی۔ آج دیش کی آرتھک استھتی بگڑتی جارہی ہے اور اسکے لئے آرتھک نیتی جوابدہ ہے۔ کتنے دن تک آپ پیوند لگا کر کام کو چلائینگے۔ بہت بحث ہو چکی ہے ہو کیا رہا ہے۔ ساری دنیا میں اور اپنے دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ مہنگائی بڑھتی چلی جارہی ہے۔ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جارہی ہیں۔ مدرا اسفیتی بڑھتی چلی جارہی ہے اور جب آپ گھاٹے کا بجٹ پیش کرینگے تو مدرا اسفیتی اور مہنگائی اور بڑھ جائیگی۔ اس گھاٹے کے بجٹ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے مدرا اسفیتی اور مدرا اسفیتی کے معنی ہیں چیزوں کی قیمت کا بڑھنا۔ اسکو آپ روک سکتے ہیں کیا۔ یہ تو

اور لیکویڈ سرکلا کے ذریعے اس استھتی کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں۔

اسکے لئے سمارو جنک و قرض پرنالی کو بھی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے جب تک آپ سمارو جنک و قرض پرنالی کو مضبوط نہیں بنائیں گے۔ تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کی ایک بہت پرانی مانگ تھی کہ لہ آو شیئر و سیکیورٹیز بی۔ ڈی۔ ایس۔ کے مادھیم سے جنتا کو دی جائیں۔ میں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر ضروری وسیکیورٹیز۔ آپ سمارو جنک و قرض پرنالی کے مادھیم سے سرکاری دوکانوں کے ذریعے اگر مہیا کرائینگے۔ تو نشچت طور پر چور بازاریوں اور جمع خوروں کو قیمت بڑھانے کا موقع نہیں ملیگا اسلئے میرا سجھاؤ ہے کہ بی۔ ڈی۔ ایس۔ کو آپ مضبوط کیجئے اور ان لہ آو شیئر و سیکیورٹیز کو اس کے مادھیم سے عام جنتا کو مہیا کرائیے۔ دھنیہ واد۔ اتنم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ غریبی کی ریکھا سے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم بی۔ ڈی۔ ایس کے مادھیم سے چیزیں مہیا کرائیں گے۔ ہم لوگوں نے اسکا سواگت کیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ کب تک کر دینگے۔ میں کھادیہ منتری جی سے اور سرکار سے مانگ کیا ہوگا کہ ۲۰ لاکھ ٹن آپ آیات کرنے والے ہیں۔۔۔۔

اب سبھاد ھیکشؔ شری محمد سلیم: سبھاپت کیجئے۔

شری جلال الدین انصاری: میں سبھاپت کر رہا ہوں۔ آج کیا ہو گیا کہ آپ ۲۰ لاکھ ٹن آیات کرنے والے ہیں ودیشوں سے منگانے والے ہیں۔ تو صاف صاف بتائیے کہ جب ہے ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ودیش کو دینگے۔ کہاں سے دینگے۔ کبھی آئی گی اچانک تو ودیش سے لائینگے۔ اسکے کیا معنی ہیں۔ آپ اسپشٹ طور پر جنتا کو بتائیے۔ سدن کو بتائیے کہ آخر استھتی کیا ہے ہم ابھی تک کہتے ہیں کہ وافر اسٹاک ہے۔ ہم کھلانے میں سکشم ہیں۔ تو کہاں کھلا رہے ہیں۔ لوگوں کو تو مل ہی نہیں رہا ہے کہاں کھا رہے ہیں۔ پرچز نگ چاول گھٹ گئی ہے۔ کریے شکتی گھٹ گئی ہے۔ پیسہ لیکر ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن ادھک قیمت پر بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس استھتی کو ختم کیا جائے اور میرا سجھاؤ ہے کہ جمع خوروں اور کالا بازاروں کے خلاف آپ کارروائی کریں اور اسمیں راجیہ سرکاروں کا بھی سہیوگ لیں۔ جب تک آپ اس پر روک نہیں لگائینگے۔ یہ کام نہیں ہوگا۔ اسلئے آپ اس بات پر وچار کیجئے کہ آپ اسکو کر سکتے ہیں۔ یا نہیں یا جیوں

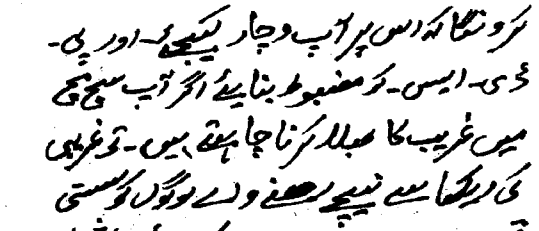

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में महंगाई के संदर्भ में चल रही चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अभी कुछ माननीय सदस्य इस बहस में हिस्सा लेते हुए कुछ राज्य सरकारों पर दोषारोपण कर रहे थे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक राज्य में महंगाई बढ़ी है और दूसरी राज्य में महंगाई घटी है। महंगाई एक राष्ट्रीय समस्या है और यह सारे देश में बढ़ रही है और आज से नहीं बढ़ रही है, पहले से बढ़ रही है। अगर हम पिछले 100 सालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 100 सालों से महंगाई बढ़ती जा रही है। गेहूं के दाम भी बढ़े हैं और अचानक बढ़े हैं और बहुत ज्यादा बढ़े हैं। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि गेहूं का इंपोर्ट किया जाए, आयात किया जाए। जैसी मुझे जानकारी मिली है और हमारे मंत्री महोदय ने भी बताया है कि 20 लाख टन गेहूं का आयात किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो 20 लाख टन गेहूं का आयात किया जा रहा है, वह कब तक हो जाएगा?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमाल सिन्हा) पीठासीन हुईं)

आयात करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जितना वक्त लगेगा उस हिसाब से हमारी आशंका यह है कि जिस दिन गेहूं का स्टॉक हमारे यहां आएगा और मार्किट में वह वितरित होगा उस समय तक हमारी फसलें तैयार हो जाएंगी। यानी फिर हमारे किसानों को जो आयातित गेहूं होगा उसके साथ कम्पीट करना पड़ेगा और फिर उनके गेहूं का दाम सही नहीं मिल पाएगा। यानी पहले भी हमारे किसान नुकसान में थे, धोके में थे, इसके बाद भी हमारे किसान नुकसान और धोके में रहेंगे। तो मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर गेहूं आयात करना ही है तो जल्दी आयात करें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि गेहूं आयात करने से पहले पूरे देश में अन्य राज्यों में जो एफ०सी०आई० के गोडानस हैं उनमें गेहूं का क्या स्टॉक है, उसकी पूरी जानकारी लें। ठीक है, दिल्ली में स्टॉक पूरा नहीं है, मुम्बई के बारे में भी कहा जा रहा है कि नहीं है। हालांकि मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि दिल्ली और मुम्बई को या बाकी अन्य शहरों को, अन्य स्थानों को, अन्य राज्यों में गेहूं सप्लाई करने के लिए दूसरे राज्यों के स्टॉक का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें अक्सर आती रही है कि हमारे एफ०सी०आई० के गोडाउन में गेहूं जरूरत से ज्यादा है और कई बार यह कहा जाता है कि गेहूं सड़ रहा है या वहां पर हमारे खाद्यान सड़ रहे हैं। हालांकि एक तरफ हमारे खाद्यान सड़ रहे है इस तरह के आरोप लगते है, इस तरह की खबरें आती हैं और दूसरी तरफ हम उनकी स्केअरसिटी की बात करते है, उनकी कमी की बात करते है, उनकी अनुपलब्धता की बात करते है। तो मुझे लगता है कि अगर सही ढंग से ध्यान दे तो इंपोर्ट करने के बजाय जो उपलब्ध स्टॉक है उसका सही ढंग से वितरण हो सकता है। मेरी जो दूसरी आशंका है वह यह है कि कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले इसी तरह शक्कर का भी भाव बढ़ा था और बहुत आर्टिफिसल तरीके से शक्कर के भाव में उछाल आया था और जब उसकी छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा शुगर स्केंडल हुआ है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह जानकारी करें कि गेहूं के अचानक बढ़े दामों के पीछे शायद उन्हें कोई नया स्केंडल मिल जाय जिसको व्हीट स्केंडल के नाम से यह देश जानने लगेगा। मैं यह भी मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत यह है कि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो मंहगाई बढ़ती है, दाम बढ़ते है। यह सप्लाई जानबूझकर कम की जाती है। सप्लाई कम करने वाले और कोई नहीं, हमारे देश के, हमारे शहर के, हमारे राज्य के जमाखोर और बेईमान व्यापारी लोग हैं। निश्चित तौर पर व्यापारी और जमाखोरों के बीच एक तरह का नेक्सस है। वह नेक्सस कौन सा है, वह नेक्सस क्यों अब तक सक्रिय है? उस नेक्सस को तोड़ने के लिए हमारी सरकार क्या

कदम उठाती है? अगर उस नेक्सस को एक्सपोज किया जाए, उसका भंडाभोड किया जाए, उसका पर्दाफास किया जाए तो शायद हमें यह जानकारी मिल पाएगी कि दरसल वास्तविक अर्थों में गेहूं की सप्लाई कम नहीं है, गेहूं की उपलब्धता कम नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि इस दिशा में भी सोचें।

मैं एक और जानकारी मंत्री महोदय और इस सदन को देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने शिव सेना-भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अच्छी परम्परा शुरु की है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में। जिस दिन हमारी सरकार वहां सत्ता में आई उस सरकार ने घोषणा की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जो 5 जीवन हेतु आवश्यक वस्तुओं का वितरण होता है गेहूं चावल, दाल, केरोसीन वगैरह, उन पांच जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम आगे आने वाले पांच सालों में नहीं बढ़ेगे। जो दाम, जो भाव, जो दर उन 5 एसिएंशल कमोडिटीज के उस समय थे, दो साल पहले थे, पौने दो साल पहले थे वही भाव, वही दर आज भी उपलब्ध है और हमारी महाराष्ट्र सरकार का यह संकल्प है कि आने वाले तीन सालों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जो पांच जीवन आवश्यक वस्तुओं का वितरण हो रहा है उनके दाम नहीं बढ़े हैं। तो महाराष्ट्र सरकार का यह जो नॉवल आइडिया है, जो एक आदर्श प्रयोग है वह प्रयोग हम राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रयोग से अंततः गरीब आदमी लाभांवित होता है, उस गरीब आदमी को फायदा होता है जो सचमुच गरीबी के मार्ग में जी रहा है। अगर चार रुपए का गेहूं चार हो जाए और पांच रुपए का गेहूं साढ़े पांच हो जाए, तो जिसके सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है।

तो हम उन गरीब लोगों के बारे में सोचें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए कई माननीय सदस्यों ने कहा। मैं भी मानता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है लेकिन इसके साथ अगर खुले बाज़ार में खाद्यान्नों के दामों पर हमें कंट्रोल करना है तो मैं चाहूंगा कि खुले बाज़ार में वितरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उस प्रणाली को भी रिव्यू किया जाए, उस प्रणाली पर फिर से विचार किया जाए। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े गायक और नायक किशोर कुमार जी ने दो फिल्में बनाई थीं जिनका नाम था "चलती का नाम गाड़ी" और "बढ़ती का नाम दाढ़ी"। अगर आज वे होते तो शायद एक और फिल्म बनाते "बढ़ती का नाम महंगाई"। जो महंगाई के नाम पर हमारी एक सोच बन रही है, एक धारणा बन रही है, उस धारणा को बदलिए और महंगाई को हटाने की कोशिश कीजिए। इसकी छानबीन भी कीजिए कि इस महंगाई का कोई नाता इकानॉमिक लिब्रलाइज़ेशन से तो नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि इकानामिक लिब्रलाइज़ेशन से, आर्थिक उदारीकरण से इसका किसी न किसी प्रकार का नाता है। उस नाते को इवैल्युएट किया जाए, रिव्यू किया जाए, छान-बीन की जाए तो शायद हम महंगाई को लेकर एक नया विचार, एक नई सोच, एक नई धारणा अपने समाज में, अपने देश में रख सकते हैं। धन्यवाद।

SHRI R.K. KUMAR (TAMIL NADU): Madam, price of any commodity goes up and down according to the demand and supply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Kumar, please be brief.

SHRI R.K. KUMAR: Madam, I will take only two minutes. I will be to the point.

In respect of essential commodities the problem is compounded further by the dual price system, i.e. one price for PDS and one price for open market. Madam, supply again depends on production. No doubt, agriculture production has been going down for the last two years.

The buffer stock is being operated exactly for this purpose. As you all know, demand cannot increase overnight beyond certain proportions. It is the erratic supply that is making the price rise beyond certain limitations both in the PDS and in the open market. Two days back we were discussing about the wheat price. The whole House was concerned about the wheat price in Delhi. I come from Tamil Nadu and as a rice-eater, I am very much concerned with the price rise of rice in Tamil Nadu; it was around Rs. 12/- per kilogram six months back, just before the elections and today the price is Rs. 19/-.

As a matter of fact, during the election campaign the Tamil Nadu Chief Minister put it very nicely that the prices were

playing with the clouds and the sky. That is one of this film songs which was written by him in his old films. But after six months prices have gone beyond the sky and clouds and they are touching the moon and the mars. I would request the hon. Minister to kindly ensure the operation of the buffer stock mechanism and also direct the State to take very stringent measures so that, at least, further rise in prices could be arrested.

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने व्हीट के बारे में तो बताया कि आप क्या-क्या कर रहे हैं व्हीट प्राइसेज को कम करने के लिए। उसी तरह से चावल के बारे में भी आप बताइए कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं चावल के प्राइसेज को कम करने के लिए?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): नरेन्द्र मोहन जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): जी हां। उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह जानता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो असफल हुई है, वह बढ़ते हुए खाद्य मूल्यों की वजह से हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगर सफल हुई होती तो शायद ये खाद्य मूल्य बढ़ने न पाते लेकिन प्रश्न यहां यह है कि दोषी कौन है? खाद्य मंत्रालय दोषी है या भारतीय खाद्य निगम दोषी है या वित्त मंत्रालय दोषी है या वाणिज्य मंत्रालय दोषी है? दोष कहां है? इसी वर्ष के आरंभ में यह निर्णय लिया गया था कि देश में जो खाद्यान्न उत्पन्न होता है, उसका छः या सात प्रतिशत निर्यात कर दिया जाएगा और "गेहूं निर्यात वर्ष" के रूप में यह वर्ष मनाया जाएगा और गेहूं निर्यात होता रहा। अगस्त के महीने में गेहूं के मूल्य आसमान छूने लगे फिर भी गेहूं का निर्यात होता रहा। यह सरकार आ गयी, फिर भी सरकार ने गेहूं के निर्यात को उस समय नहीं रोका और निर्यात को रोकने की घोषणा खाद्य मंत्री जी ने संभवतः 10 दिसम्बर को उस समय की जब हमारे भाई गुरुदास जी ने उस पर चर्चा की और कहा कि भारतीय खाद्य निगम में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। सारी कठिनाई यह है कि खाद्य निगम, खाद्य सचिव और वाणिज्य मंत्रालय के बीच में कहीं कोई तारतम्यता नहीं दिखाई देती। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण को देखें, जो इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण रिजर्व बैंक ने पब्लिश किया है उसके अनुसार तो हमारे यहां बहुत खाद्यान्न होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): नरेन्द्र मोहन जी, संक्षेप में कहिए।

श्री नरेन्द्र मोहन: महोदया, मैं दो मिनट लेना चाहूंगा। सर्वेक्षण के अनुसार तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन बहुत बढ़ जाना चाहिए पर क्या बात हुई है? जो रिजर्व बैंक का प्रकाशित परिपत्र है और आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार खाद्यान्न उत्पादन पहले से अच्छा होना चाहिए फिर यह क्यों घट गया? खाद्यान्न उत्पादन घट गया या प्रेक्योरमेंट घट गया, इसके सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है, यह खाद्य मंत्री जी बताएं और यह भी बताएं कि गेहूं कहां गया? 270 लाख टन गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आज के दिन भी इकट्ठा है, फिर भी वह गेहूं और चावल उपभोक्ता तक क्यों नहीं पहुंचा, इसका सीधा उत्तर दें। क्या खाद्य निगम के गोदाम खाली हो गये थे? कहां कठिनाई आयी? गांव तक खाद्यान्न क्यों नहीं पहुंचा जो खाद्य निगम के गोदामों में है? खाद्य निगम के गोदामों से उन्हें गेहूं दिया गया जो बड़े-बड़े फ्लोर मिल्स थे ताकि वह गेहूं का आटा बनाकर उसका निर्यात कर सके। यह कहां की नीति है? फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो कमियां आती चली जा रही थीं, इसकी जानकारी अगस्त के महीने में हो गयी थी कि राज्य सरकारें नहीं उठा रही है। यह ठीक है कि खाद्य मंत्रालय ने लगभग 111 लाख टन गेहूं राज्य सरकारों को आबंटित किया और राज्य सरकारों ने संभवतः 55 लाख टन गेहूं उठाया, बाकी नहीं उठाया। ठीक है कि राज्य सरकारें दोषी हैं लेकिन भारत के खाद्य मंत्रालय ने इस बात की मानीटरिंग क्यों नहीं की कि राज्य सरकारें गेहूं समय पर क्यों नहीं उठा रही हैं? आखिर कोई तो आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार आबंटन कर दिया गया। हां, तमिलनाडु ने जितना मांगा था, उतना नहीं दिया गया लेकिन जो दिया गया, उतना भी तमिलनाडु ने चावल नहीं उठाया। राज्य सरकारें मांगने के बाद भी खाद्यान्न नहीं उठाती है, उसको रोकने की क्या व्यवस्था है? इस पर कोई चर्चा होनी चाहिए। खाद्य मंत्री इसका भी उत्तर दें। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): डा० रणबीर सिंह, आप बहुत संक्षेप में दो मिनट में बोलिए।

डा० रणबीर सिंह (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद मैडम, आज हम लोग एक बहुत सीरियस नेशनल प्राब्लम यहां डिसकस कर रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब एक माननीय सदय ने कहा कि कमी भी नहीं है और महंगाई भी नहीं है, सिर्फ दिल्ली और मुम्बई में महंगाई है। मैं

बहुत खुश होता, अगर यह बात सही होती और अगर यह बात सच है तो फिर यह लूटपाट की खबर जो रोज अख़बार में पढ़ने को मिल रही है, वह लूटपाट क्यों हो रही है? एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि दिल्ली में व्यापारी लोग हैं जिन्होंने अपने गोदाम भर रखे हैं और वह गोदामों से सामान निकालते नहीं, वह लोग बी०जे०पी० के लोग हैं। उनको यह तसल्ली होनी चाहिए कि यह डिस्कशन बी०जे०पी० के मैम्बरान लेकर हाउस में आए हैं और बी०जे०पी० के मैम्बरान के अंदर इतना मोरेल करेज है कि अगर यह सच भी है कि व्यापारी बी०जे०पी० के लोग हैं, उनकी मुखालल्त भी उसूल के तौर पर हम करने को तैयार हैं जब कि दूसरे लोग शायद ऐसा नहीं करते। मैडम, अभी चंद दिन पहले मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि एफ०सी०आई० के गोदाम भरे पड़े हैं, राज्य सरकारें उन्हें उठा नहीं रही हैं। मुझे बड़ी खुशी होती, अगर यह ठीक होता और अगर यह बात सच है कि तो हम लोग इम्पोर्ट करने को क्यों तैयार हो गये हैं? क्या मजबूरी है? क्यों नहीं हम गोदामों के अंदर से अनाज निकाल लेते? क्यों नहीं उन व्यापारियों को हम पकड़ते और क्यों नहीं उनके ऊपर कानूनी शिकंजा हम लोग कसते? मैडम, किसान से 4 रुपये 30 पैसे किलो के हिसाब से गेहूं लिया गया। आटा मिलों और डबल रोटी वालों को हम लोगों ने कन्ट्रोल के भाव पर गल्ला सप्लाई किया, गेहूं सप्लाई किया, इसके बाद हमने क्यों नहीं देखा कि मिल वाले आटा किस रेट पर बेच रहे हैं और डबल रोटी का रेट क्यों इतना आसमान छू रहा है। मल्होत्रा जी ने बताया कि 12 रुपये में डबल रोटी मिल रही है। अभी दो-तीन दिन पहले एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था कि at present there is no control on the manufacture of bread in the country.

मैं समझता हूं कि जब आटा हम उनको सही रेट पर दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं प्राइज को मॉनिटर करते? मिनिस्ट्री को इसे करना चाहिये। पीडीएस सिस्टम अगर एफिशियेन्टली काम करे तो इसके दो फायदे हैं एक तो गरीब आदमी को आटा पहुंच जाता है, अनाज पहुंच जाता है, खाने की चीजें मिल जाती हैं और वह महंगाई को भी रोकता है। अब ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं। गरीब आदमी भूखों पर मर रहे हैं मालदार आदमी के ऊपर शायद प्राइस राइज का असर पड़े न पड़े लेकिन जो भूखों मरने वाले लोग हैं वे सारे के सारे गरीब लोग हैं। हम लोग गेहूं भी एक्सपोर्ट करते हैं और आटा भी एक्सपोर्ट करते हैं। गेहूं पर शायद अब रोक लग गई है, आटे पर लगी या नहीं, मुझे पता नहीं। मेरा ख्याल है कि शायद आटे पर भी हम लोगों ने रोक नहीं लगाई है।

एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्राइसेस हैं वे भी लागू हो रहे हैं। हम जब भी सप्लाई करते हैं, गेहूं की गोडाउन्स से गेहूं के दाम वे बढ़ा देते हैं तो क्या खुले बाजार में हम यह आशा करें कि हमारे एफ०सी०आई० के गोदामों से उसका प्राइस बढ़ जाये और खुले बाजार में प्राइस न बढ़े, लो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

एक जगह हम लोग और फेल हो रहे हैं। जिसकी वजह से खाने में और अनाज में कमी पड़ेगी पापुलेशन कन्ट्रोल, से। पापुलेशन के ऊपर हमारे यहां कोई कंट्रोल नहीं है और जो खाद्य की उपज है पापुलेशन करीब-करीब उससे कुछ ज्यादा बढ़ रही है, हमारा खाद्यान्न उस रेट से नहीं बढ़ रहा है और अगर यही हालत रही तो कुछ दिनों के बाद यहां की पापुलेशन को खाना मुहैया करना मुश्किल हो जायेगा।

अभी पैट्रोलियम प्रोडेक्ट्स में हमने प्राइसेस बढ़ायी थी और फिर अब चर्चा आती है, कभी-कभी कहीं से सुनने को मिलता है कि फिर बढ़ेगा, इसका भी खाने के ऊपर खराब असर पड़ेगा, एडवर्स असर पड़ेगा अच्छी एग्रीकल्चर की जो जमीन है आबादी में जा रही है, इंडस्ट्रीज उसके ऊपर कायम हो रही हैं और कुछ ऐसी फसलों में भूमि डायवर्स हो रही हैं जो अनाज से संबंधित नहीं है, मनी क्राप्स हैं। अगर इस तरीके से जमीन कम होती चली गई तो मुझे लगता है कि खाने की और ज्यादा कमी पड़ेगी।

फर्टिलाइजर हमको ठीक से मिलता नहीं है। पीछे पोटाश की बहुत कमी थी और हुआ यह कि किसानों ने इम्बेलेन्स फर्टिलाइजर का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया उससे पैदावार तो हमारी घटी ही लेकिन जमीन भी हमारी बेकार होती चली गई। अभी हाल में जो शुगर मिल हमारी चली हैं ये करीब एक महीना लेट चली हैं और छोटा किसान ईख काटने के बाद गेहूं बोता है। एक महीने की देरी होने से शुगरकेन का खेत में खड़े रहने की वजह से मौसम निकल गया और गेहूं नहीं बोया गया। अगले साल मुझे ऐसा लगता है और भी कम गेहूं पैदा होगा और यह समस्या हमारी और बढ़ेगी। पानी का इंतजाम किसानों के लिए ठीक नहीं है। जैसा कल सोमपाल जी ने बताया था हमारी नहरों की सफाई नहीं की जाती तो जो कैपेसिटी हमारे नहरों की प्रेजेन्ट है, उतना भी उनसे एफिशियेन्सी के साथ इरिगेशन नहीं किया जाता और नहरें तो बढ़ाई नहीं जा रही हैं। वैसे जरूरत इस बात की है कि अगर हमारी खेती को पानी मुहैया

कराने की कोशिश की जाये या इंतजाम किया जाये तो बहुत कुछ हम लोग पैदा कर सकते हैं। अब मेरा सुझाव है अगर हमको सैल्फ सफिशियेन्ट फूड में रहना है, तो पापुलेशन के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है, इरिगेशन का इंतजाम होना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है अगर इरिगेशन का इंतजाम हो जाये तो अकेला राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान को खाना मुहैया कर सकता है। हमारे पास 18 करोड़ हेक्टेयर जमीन है जो कल्टीवेबल है, जिस पर खेती की जा सकती है। लेकिन हमारे यहां खेती सिर्फ 14 करोड़ हैक्टेयर जमीन में की जा रही है और बाकी 4 करोड़ हैक्टेयर जमीन हमारे पास ऐसी ही पड़ी हुई है जिसको कृषि के अंदर लाने की जरूरत है।

एक्सपोर्ट हमको बड़े एन्टीसिपेशन के साथ करना चाहिए, बड़ी समझदारी के साथ करना चाहिए। हमारा इतना एन्टीसिपेशन होना चाहिए कि हमारे पास कितना अनाज है और हमें जनता के लिये कितनी जरूरत है। इसको समझने के बाद ही हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें।

फर्टिलाइजर और अच्छे बीजों की उपलब्धता किसानों को कराना बहुत जरूरी है। इसके वगैर, हम समझते हैं कि अन्न की हर साल कमी रहेगी और यह प्राब्लम हम लोगों की हमेशा बनी रहेगी।

मैडम, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): उपसभाध्यक्ष महोदया, एक दर्जन से ज्यादा माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर....

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) मंत्री जी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो सी०पी०एम० के एक साथी एक-दो सुझाव देना चाहते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ठीक है, मैं एग्री करता हूं।

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Hon. Madam Vice-Chairman, I only want to submit a few points.

एक माननीय सदस्य: इनको कैसे इजाजत दी गई?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): जिस तरह से नरेन्द्र मोहन जी को इजाजत दी गई, उसी तरह से इनको भी दी गई।

SHRI BRATIN SENGUPTA: Madam, rise in prices is a continuous phenomenon in our country. It is nothing new. But the most affected sections of our people are those who are not covered by any kind of insurance against rise in prices. They are the agricultural labourers, daily wage earners, housewives students, youth, etc. For example, prices of newsprint, books, literature, different forms of journals, even cinema tickets, have been under rise continuously for all these years.

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): Mr. Sengupta, we are discussing the steep rise in the prices of essential commodities. I don't think cinema tickets are essential commodities. Come to the point.

SHRI BRATIN SENGUPTA: Madam, the price of newsprint is being hiked at regular intervals. It is rising continuously for all these years...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): Kindly don't make any comments. Let him finish.

SHRI BRATIN SENGUPTA: I would request the hon. Minister to kindly take notice of the rise in the prices of other essential items and to think of some kind of an insurance for the uninsured sections of our society who are the worst hit because of the rise in the prices of essential commodities.

श्री देवेन्द्र यादव: महोदया, मैंने पहले ही जिक्र किया कि मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन माननीय सदस्यों ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा उठाई है और खास करके प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी, जिन्होंने इस चर्चा को इनिशियेट किया है। अभी जो परिस्थिति है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। लेकिन यह समस्या दलों से ऊपर उठकर विचार करने की है अभी मैंने इस बात का जिक्र किया और अभी एक माननीय सदस्य ने सी०आई०पी० की चर्चा की सेंट्रल इश्यू प्राइस की चर्चा की। सेंट्रल इश्यू प्राइस फरवरी, 1994 के बाद बढ़ाया नहीं गया, इसकी चर्चा की गई। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की

लोगों की प्रति, इस सदन के प्रति एक एकाउंटेबिलिटी है। इस देश में जो महंगाई हो रही है उसके लिए हम, केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है, हमारी एकाउंटेबिलिटी है, हमारी जवाबदेही है। लेकिन जवाबदेही में तथ्यों को तोड़मरोड़कर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि गेहूं के दाम आज पी०डी०एस० में, यहां पर जन वितरण प्रणाली की बहुत चर्चा हुई। कमोवेश में सभी माननीय सदस्यों ने जन-वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने, उसको मजबूत बनाने की ओर इशारा किया है। इसलिए मैं इसको पहले लेता हूं गेहूं का दाम क्या जन वितरण प्रणाली में केन्द्र सरकार ने बढ़ाया है? कोई माननीय सदस्य इसका जवाब दें तो मैं इसका स्वागत करूंगा। **(व्यवधान)** जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप लोगों ने जो बातें कहीं वह मंत्री जी ने सुनी। आप लोग उनका जवाब भी सुनिये **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, उनका जवाब भी सुनना चाहिये, यही तरीका है **(व्यवधान)**

SHRI V. NARAYANASAMY: In your statement you have said that your Government has increased the wheat price. You accept it and then speak.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह गलत बात है **(व्यवधान)** नारायणसामी जी, मैं आ रहा हूं **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): Mr. Narayanasamy, kindly have patience and hear what the Minister has to say. You have said what you wanted to say. *(Interruptions)* Please have some patience.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदया, जन वितरण प्रणाली संचालन के दो स्तम्भ हैं, दो तरीके हैं, दो तरह से यह संचालित होती है। केन्द्र सरकर की कुछ जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों की भी कुछ जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी जन वितरण प्रणाली में सिर्फ आबंटन देने की है, यहां लकीर खिंच जाती है। किन राज्यों को कितना आबंटन मिलना चाहिये, यह केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है, केन्द्र सरकार के अधिकार में है। केन्द्र सरकार किन राज्यों को कितनी आवश्यकता है इसको देखते हुए जैसे दक्षिण के कुछ स्टेट्स डेफिसिट स्टेट्स हैं, उनकी समस्याओं को भी देखना पड़ता है। फिर जो राज्य आफ-टेक करते हैं, उनकी जरूरत को भी देखना पड़ता है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए खासकर के कहीं अकाल की परिस्थिति हो गई, स्टारवेशन और प्राकृतिक आपदा अथवा नेचुरल केलेमिटी पैदा हो गई तो केन्द्र सरकार विशेष व्यवस्था करती है, हिस्टोरिकल अलाटमेंट के बावजूद भी एलोकेशन करना पड़ता है तो केन्द्र सरकार करती है, जन वितरण प्रणाली का जो एलोकेशन है, जो अलाटमेंट है, वह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। महोदया, नीचे की राशन की दुकानों पर मुहैया हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह काम सिर्फ राज्य सरकारों का है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को स्पष्ट समझ लेना चाहिये। बहुत ज़ोर से आज हल्ला हो रहा है। महोदया, आप जानती हैं कि 20 साल से पहले 1977 से इस्तीफे की राजनीति से मैंने शुरू किया था जब कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर हुए थे तो मैंने असेम्बली छोड़ी थी। 1974 के आन्दोलन में मैं आया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आन्दोलन के नेतृत्व के गर्भ से पैदा होकर आया था। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अचरच नहीं है, ठीक है, सरकार है, हमको जो सुझाव आएंगे, उनको गम्भीरता से लेना है। लेकिन ऐसी बात की जाती है, ने केवल सदन की मर्यादा के विपरीत बल्कि इतना गैरजिम्मेदाराना बातें हो रही है। कोई भी जिम्मेदार पद पर रह कर सदन के कोई माननीय सदस्य बिना प्रमाण के, बिना स्पेसेफिक जानकारी के यों ही फ्लोट कर रहे हैं, पोलिटिकल कलर दे रहे हैं, गेहूं का हौवा खड़ा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तथ्यों को आप रखिये, आपको पूरी आजादी है, सदन में सारे तथ्यों को आप रख दीजिये। जांच हो सकती है, सदन की समिति बन सकती है। चतुर्वेदी जी नहीं तो आप ही की पार्टी के सदस्य को वहां पर बना देंगे। हम तैयार हैं, सरकार तैयार है **(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: बनाइये, हम तैयार है **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः विजय कुमार जी जब आप बोले रहे थे **(व्यवधान)** मैं तैयार हूं। जो आपके पास एक्सपर्ट आदमी है, हो जाए, मैं बिलकुल तैयार हूं। सांच को आंच क्या है, हो जाए जांच **(व्यवधान)** सरकार एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहती है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी दल से जांच करवा लें, हम तैयार हैं। खाद्य मंत्री होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, यदि मेरे महकमे में किसी भी तरह की अनियमितता हुई हो, इरेरेगुलरिटी हुई हो तो मेरी उसकी जिम्मेदारी है, संयुक्त रूप से हम को जिम्मेदारी लेनी चाहिये। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं **(व्यवधान)**

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः आप बना क्यों नहीं रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः सुनिये, सुनिये **(व्यवधान)** आप पहले मेरी बात सुनिये, बीच में मत बोलिये (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): एक मिनट **(व्यवधान)**

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: But he has offered it. *(Interruptions)* He has offered it, Madam.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी आप आसन ग्रहण करें **(व्यवधान)** मल्होत्रा जी आप आसन ग्रहण करें। **(व्यवधान)** मंत्री जी ने स्वयं कहा, आवश्यक होगा तो समिति बनाने के लिए तैयार हैं **(व्यवधान)**

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः बनाइये **(व्यवधान)** We accept the offer.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): ठीक है, उन्होंने स्वयं कहा। इस बात की हम चर्चा कर लेंगे, चेयरमैन को कहिये, इनको कहिये, यहां शोर मचाने की जरूरत नहीं है **(व्यवधान)** ठीक है, इन्होंने कह दिया **(व्यवधान)**

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Let him announce it then.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी ने कहा है। मंत्री जी की सदन में घोषणा है न। मंत्री जी ने सदन में घोषणा की है। आप मंत्री जी से बात कर लें। हम लोग भी बात कर लेंगे। समिति बना देंगे। लेकिन इनको वक्तव्य पूरा करने दें। **(व्यवधान)** Kindly sit down *(Interruptions)* Narayanasamyji, kindly sit down. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I am going to the assistance of the hon. Minister. Nobody charged the Minister. This is number one ...*(Interruptions)*...

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV: Madam...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Minister, you don't react. Please sit down ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Secondly, the hon. Members said that the price of wheat in the international market has gone up to 157 dollars and they are purchasing it. This is what they said. I said that you should purchase it at competitive rates. They should not challenge us. The Minister should tell the reality. ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः एफ॰ सी॰ आई॰ ने जो बंगलिंग की है, एपाइंट द कमेटी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः नारायणसामी जी ने मेरा ध्यान खींचा है कि तथ्यों को रखा जाए। चार्ज नहीं लगाया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं । विजय कुमार जी बहुत सीनियर नेता है। उन्होंने अभी एफ॰सी॰आई॰ के विषय में कहा। विजय कुमारजी, में और आप जन-प्रतिनिधि हैं।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः अभी तो एफ॰सी॰ आई॰ को सी॰बी॰आई॰ ने पकड़ा है... **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः आप सुनिए तो।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप अपनी बात कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः पहली बार मैं मंत्री हुआ हूं। पूर्व उदाहरण होगा, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जो बुद्धि है उसी हिसाब से जवाब दूंगा...**(व्यवधान)** बुद्धि में गड़बड़ी हो सकती है, हमारी नीयत में कभी भी या संयुक्त मोर्चे की सरकार में नहीं हो सकती है। कुछ

लोगों की नीयत में भी गड़बड़ी है और बुद्धि में भी गड़बड़ी है। वह तो मेरी बुद्धि के बाहर की बात है। मेरी बुद्धि में जो बात है वह मैं कहना चाहता हूं। जब से मैंने कार्यभार संभाला है लोग बोलते हैं समय से कार्यवाही नहीं

की। चढ़ी जोर से बोलते हैं। समय से कार्यवाही क्या की है वह स्टेप मैं बाद में बताऊंगा। क्या क्या पहल मैंने शुरू से की है यह तथ्यात्मक जानकारी मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। सदन सर्वोपरि है। जब मैं हुआ तो मुझे दो जानकारियां मिलीं। अनियमितता, इरेग्युलरिटी और भ्रष्टाचार की जानकारी मुझे एफ०सी०आई० के महकमे में जो मिली थी, उसमें केवल दो मेरे संज्ञान में आई। मैंने उसी क्षण आदेश किया कि इन दोनों मामलों में नीचे के स्तर से जांच नहीं हो सकती। यह हम सी०बी०आई० को सुपुर्द करते हैं और हमने दिया पंजाब? के मामले को। जहां मामला गड़बड़ है, जिसका अनुसंधान सी०बी०आई० के अंदर है इस बाबत मुझे आगे कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वह अनुसंधान में है, इन्वेस्टीगेशन में है। सी०बी०आई० इन्वेस्टीगेट कर रही है। वह मामला क्या है? स्टाक को कम करने का है। किसी भी कीमत पर किसी भी अधिकारी को, बड़े से बड़े अधिकारी को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश के अनाज को, खजाने को किसी भी तरह से कम करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने सी०बी०आई० को दिया। दूसरा मामला कहां से दिया? आप लोग बोल रहे हैं अफसोस है। सारी कलई बस खुलने वाली है। कौन लोग हैं इसमें? बड़े मिलर वाले हैं। रोलर फ्लोर मिल वाले हैं। हरियाणा का मैंने दे दिया है—जहां कौन लोग लेते थे एलाटमेंट? एलाटमेंट में गड़बड़ी होती थी। यह जानकारी मुझको है। सब तरह से जानकारी है। छोटे अफसर को सस्पेंड करो, इसको करो उसको करो क्लास टू को, क्लास थ्री को, हमने कहा, नो नो आई एम नाट सैटिसफाइड। में संतुष्ट नहीं हूं इस कार्यवाही से। आप कोई और उदाहरण बताइए, किसी मंत्री ने कभी ऐसे किया। पिछले जमाने में क्या हुआ, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी नालेज में नहीं है। वह मुझे देखना पड़ेगा, मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने इस केस को दिया जो हरियाणा सरकार ने रेफर किया था। वह भी चला गया। दो केस तो सी०बी०आई० में चले गए और यह जो शिवचरण जी ने कहा। माफ करिएगा, माननीय सदस्य जी, आप राजस्थान के हैं, आपको मालूम है 12 घंटे के भीतर मैंने वहां विजिलैंस बैठा दिया। उसकी रिपोर्ट कल तक प्राप्त हो जाएगी जो वहां राजस्थान में हुआ, जो माननीय सदस्य ने पिछले दिन जब मैं वक्तव्य देने आया था उस दिन उठाया था। इतनी जल्दी किया। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार से संयुक्त मोर्चे की सरकार का कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं भ्रष्टाचार के मामले में इतनी दूर तक जा सकता हूं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करके कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं। कहते हैं कार्यवाही कीजिए। हमारे नारायणसामी जी ने कार्यवाही की चर्चा की। मैं पहले पी०डी०एस० की चर्चा अभी कर देता हूं। पी०डी०एस० में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है—मानीटरिंग करने की, निगरानी करने की, नीचे की दुकानों में राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा उसके इंस्पेक्शन की, सस्ते गल्ले की दुकानों की नियुक्ति करने की भी। सस्ते गल्ले की दुकान में जो सामान बांटने वाले डीलर्स हैं उनकी भी नियुक्ति वहां के डी०एम० करेंगे और राज्य सरकार के अधीन जो अधिकारी हैं उनके अंदर है। हमारा काम सिर्फ आवंटन है। लेकिन आज पूरे देश में यह हल्ला हो रहा है—जन वितरण, जन वितरण में केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की सीमाएं हैं काम करने की...

श्री नरेन्द्र मोहन: एक क्लैरीफिकेशन लेना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपकी बात पर अभी आ रहा हूं। मैं बोलूंगा सारी बात खोल दूंगा सदन में, कोई बात नहीं रखूंगा। मैंने पहले ही कहा कि में ट्रांसपैरेंसी में विलीव करता हूं। हम पारदर्शी सिद्धांत में विश्वास करते हैं, यह मैं सदन को साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं। अभी पी०डी०एस० के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जो राज्य सरकार की निगरानी का काम है, राज्य सरकार सस्ते गल्ले की दुकान की नियुक्ति भी करेगी। सस्ते गल्ले की दुकान पर मॉनिटरिंग, निगरानी पंचायत लेवल पर, ब्लाक लेवल पर, वार्ड लेवल पर उन्हीं को करनी है। हमारा काम तो सिर्फ राज्य को, उसकी सिविल सप्लायी कार्पोरेशन जो है, उनको सिर्फ आवंटन तक देना है, एलोकेशन तक देना है। बड़ा शोर मचता है कि पी०डी०एस० में सामान नहीं मिल रहा है। यह किसकी जिम्मेदारी है? हृदय पर हाथ रख कर मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अपने पूरे विभाग को लगा कर मैं पांच महीने सोया नहीं हूं। मैंने यह पूरी जानकारी ली है कि पी०डी०एस० में क्या हो रहा है। पी०डी०एस० को स्ट्रीमलाइन और फाइनल करने मैं जा रहा हूं। अब तो मुश्किल से एक सप्ताह भी नहीं लगेगा। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। यही तो देवेन्द्र यादव का अपराध है कि उसने गरीबों के लिए आधे दाम पर देने की जिस दिन से योजना बनायी है उसी दिन से आफत आना शुरू हो गई है। गरीबों के लिए अगर कोई आदमी मजबूती से काम करेगा तो उसके रास्ते में कई तरह की

बाधाएं लगाई जायेंगी। चूंकि यह काम हम करना चाहते हैं हैव नॉट्स के पक्ष में, गरीब लोगों के पक्ष में करना चाहते हैं जो कि परिवर्तनकारी हैं और जो परिवर्तन नहीं चाहने वाले लोग हैं, जो स्टेटस के लोग हैं, यथास्थितिवादी लोग हैं, वे तो हल्ला मचायेंगे। सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। सरकार का समर्पण, कमिटमेंट गरीबों के प्रति है और जो लास्ट मैन आफ् द सोसायटी है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए आई शैल गो टू एनी एक्सटेंट, सरकार किसी भी दूरी तक जा सकती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार पर आज किसी तरह से बादल और कुहासा लगाया जा रहा है। बादल तो अब छंटने जा रहा है। दाम गिरना ही नहीं, छापेमारी भी चल रही है। अब तो इस देश में छापेमार का हिसाब आ गया है। आप तीन दिन और रुक जाइये। कहां जायेंगे ये कालाबाजारिए और जमाखोरिए? ठीक है, इनके पास कुछ है। बड़े-बड़े जादू हैं जादू कैसा है इसकी एक जानकारी मैं दे देना चाहता हूं। चावल की भी स्केयरसिटी खड़ी कर दी। दुर्भाग्य है। एक बड़ा नामी अखबार है, ठीक है, नरेन्द्र भाई का अखबार नहीं है। वह अखबार थोड़ा अच्छा है। आप जरा इसको देख लीजिए, "Rice stock to fall below buffer norms" बफर स्टॉक नार्म से राइस नीचे गिर रहा है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है? खाद्यान्न के मामले में किस तरह से पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। यह "द आब्जर्वर" अखबार है। कल की यह रिपोर्ट है। यह देख लीजिए। ...(व्यवधान) आप देख लीजिए, मैं नहीं कह सकता है। आन् बिहाफ आफ् द गवर्नमेंट मैं कुछ कह सकता हूं, लेकिन इसकी अच्छी जानकारी तो बी०जे०पी० को होगी। मल्होत्रा जी अच्छी तरह से जानते होंगे। एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि अननैसेसरली पैनिक क्रिएट किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट इस वर्ष हो गया 55 लाख, इन टर्म्स आफ राइस हो गया। अभी पंजाब में हमारी मशीनरी चुस्त थी, इस मामले में हम सतर्क थे, क्योंकि हमारे कार्यभार में यह काम था। पिछले साल 45 लाख टन हुआ था। एक मिलियन ज्यादा प्रोक्योरमेंट अभी हो गया और अब 77 तक जाने की उम्मीद है। अखबार लिखता है कितना, जरा देख लिया जाए। कितने बड़े हर्फों में छपा है। मैं अथेंटिसिटी तो नहीं करता हूं। इस तरह की रिपोर्ट लिखने के लिए यह उन्हीं पर मुनहसिर है। यू०पी० पिछले साल से दुगुना प्रोक्योरमेंट कर रहा है। पश्चिमी बंगाल ने भी दुगुना ही कर लिया। 7 हजार पहले किया था इस बार 9 हजार है। सभी स्टेट्स की रिपोर्ट है। प्रोक्योरमेंट इस बार बिहार में भी मैंने शुरू किया और उड़ीसा में भी इस बार हमने प्रयास किया है कि ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो। यदि खाद्यान्न का हमारे पास भंडार होगा तभी तो हम जन वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को दे पायेंगे। इसलिए हम चावल के मामले में सतर्क हैं। गेहूं के बारे में उतने नहीं हो सके इसलिए गेंहू का बादल मंडरा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गेहूं घर ले चलो और छिपाओ। इधर गेहूं हल्ला, गेहूं का अभाव, गेहूं का बड़ा अकाल है, गेहूं बड़ा महंगा है, आटा बड़ा महंगा और उधर गेहूं छिपाओ। गेहूं छिपाने वालों का भी पता मैं ले रहा हूं। उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं यहां कुछ संकल्प लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी जो काला बाजारी...(व्यवधान) नहीं, पहले मैं आपको पी०डी०एस० की जानकारी दे देना चाहता हूं। अभी गेहूं का दाम, हम पी०डी०एस० में जो सप्लायी करते हैं, केन्द्रीय सरकार जो देती है, इसका रेट 402 रुपये क्विंटल है। चार रुपये दो पैसे हम राज्य सरकारों को देते हैं। राज्य सरकारें दूरी के हिसाब से, ट्रांपोर्टेशन कास्ट, प्रचेजिंग कास्ट प्लस मंडी टैक्स जो भी जोड़कर राज्य सरकार को इस में 50 पैसा, एक रुपया या डेढ़ रुपया बढ़ाकर जन-वितरण प्रणाली में देने का अधिकार है, लेकिन मान्यवर हमारा दाम एक पैसा नहीं बढ़ा है। बड़ी जोर से हल्ला है कि सी०आई०पी० बढ़ गया, केन्द्र सरकार ने दाम बढ़ा दिया। मान्यवर, जो उन के बिल्कुल नियंत्रण में है, उस का पी०डी०एस० का दाम नहीं बढ़ाया है। गरीब लोगों को जो अनाज मुहैया होना है उस गेहूं का दाम 402 रु० क्विंटल है।

चीनी का दाम पूरे देश में एक कंजूमर प्राइस 9 रुपए 50 पैसे है। कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बढ़ रहा है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब यह कहा जाता है कि मैं तथ्यों को नहीं रखना चाहता हूं। नरेन्द्र मोहन जी चीनी से बहुत जुड़े हुए हैं और इस बैंच पर बहुत लोग चीनी से जुड़े हुए हैं। उन्हें मालूम है, पहली बार किसी राज ने चीनी का दाम घटाया है तो वह संयुक्त मोर्चा सरकार ने घटाया है वह 12 रुपए, 14 रुपए से ज्यादा नहीं है। बाहर खुले मार्केट में भी दाम घट गया है और इसीलिए वे चिंतित हैं। शुगर लॉबी की चिंता है कि यह क्या हो गया है? मंत्री जी क्या कर रहे हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और संतुलन बनाने की कोशिश करुंगा, लेकिन गरीबों के हितों की किसी भी कीमत पर सरकार की तरफ से अनदेखी नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं ने संकल्प लिया है कि चीनी का दाम 9 रुपए 50 पैसे से ज्यादा पी०डी०एस० में नहीं बढ़ेगा। इस का ऑल ओवर इंडिया एक रेट है।

महोदय, किरोसिन ऑइल का दाम हम 2 रुपए 75 पैसा देते हैं। कहीं-कहीं किसी-किसी राज्य में ट्रांसपोर्टेशन कुछ ज्यादा होने के चलते 3 रुपए प्रति किलो पड़ जाता है। पॉमोलिन ऑइल 24 रुपए के०जी० एन-ब्लॉक है। महोदय, सॉफ्ट कोक 2 लाख टन आयात किया जाने वाला है क्योंकि उस की पी०डी०एस० की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। हम सॉफ्ट कोक 175 रुपए प्रति टन देते हैं। महोदय, केवल बिहार और पश्चिम बंगाल में इस की पी०डी०एस० के लिए कुछ डिमांड है। मैं ने इस का जिक्र इसलिए किया कि पी०डी०एस० का हम ने दाम नहीं बढ़ाया है और पी०डी०एस० का राशन का जो एलोकेशन है, वह किसी भी राज्य में नहीं घटाया है बल्कि इस महीने से, इससे अगले महीने से सभी राज्यों के लिए कुछ-न-कुछ बढ़ाया है। महोदय, इस महीने में तो संपूर्ण रूप से पूरे देश में एक लाख टन पी०डी०एस० का हम ने एलोकेशन बढ़ाया है क्योंकि क्रिसमस और कुछ दूसरे पर्व-त्यौहारों की महत्ता को देखते हुए हम ने इस पर विचार किया है।

महोदय, मैं यहां तथ्यों की जानकारी देना चाहता हूं कि जहां खुले बाजार में मूल्यों में वृद्धि का सवाल है, तो यह खुले मार्केट की अर्थ-व्यवस्था किस के हाथ में है? मैं यहां कुछ सवाल छोड़ना चाहता हूं माननीय सदस्यों के विचार के लिए कि सरकार की क्या सीमाएं हैं? ओपन मार्केट में जो मैकेनिज्म है, खुले बाजार का जो मैकेनिज्म है, वह किन लोगों के हाथों में है यह आप खुद समझते हैं। कुछ तो स्वाभाविक रूप से रियलिटी में परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार और उत्पादन में कमी होने के कारण दाम बढ़ना था। तो कुछ तो कारण रियल हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बिल्कुल आर्टिफिसियल हैं। महोदय, कल मैंने जो बयान दिया था, मैं इंचभर उस से डिग नहीं सकता। मैंने कहा था कि कुछ आर्टिफिसियल या कृत्रिम तरीके से भाव को बढ़ाया गया है। आज मैं पुनः उस को संपुष्ट करता हूं कि दाम बढ़ा है समर्थन मूल्य से जो किसानों के लिए है। फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, किसान जो खेत-खलिहान में अनाज पैदा कर, उत्पादन करके पूरे मुल्क को खिलाता है, क्या उन का दाम नहीं बढ़ाया जाय? यदि उनका दाम नहीं बढ़ाते हैं तो कल उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आज जो चावल हम प्रोक्यूर करते हैं, कल उस चावल का उत्पादन नहीं हो पाएगा इसलिए यह जरूरी था और सरकार ने इसे सिद्धांततः मानकर इस रूप में कार्य किया। वह 360 रुपए से 380 रुपए किया। अब प्रोक्यूरमेंट प्राइस बढ़ गया है, समर्थन मूल्य हम ने बढ़ाया है तो हम मानकर चलते हैं कि इसके चलते जो भी हो, लेकिन जो उत्पादक है, किसान है, खेती करते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं, देश को अनाज खिलाने का काम करते हैं, उनके लिए 5 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत के लगभग गेहूं का दाम बढ़ा है। यह अनुमान विशेषज्ञों का है। फिर यातायात खर्च आता है, ठीक है आप कहेंगे इस में पेट्रोलियम भी आ जाता है। तो हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते हैं। पहले भी हमने आप से कहा है और हम इसे स्वीकार करना चाहते हैं। हम ऐसी दलील नहीं देना चाहते जोकि तथ्यों के बाहर हो, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ का इस पर इफेक्ट होगा, गेहूं पर इफेक्ट होगा। सही मायने में यातायात या ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी—यह सब मिलाकर उस की भी लगभग उसी अनुपात में वृद्धि होगी। अब जोड़ा जाए सबका तो यह 28 से 31 प्रतिशत बढ़ा। होल सेल प्राइस इण्डेक्स की चर्चा आपने की मल्होत्रा जी ने और हमारे नारायणसामी जी, माननीय सदस्य ने। गत वर्ष गेहूं की कीमत बढ़ाई नहीं गई। मैंने आपसे पहले कहा कि 2 फरवरी, 1994 के बाद तो दाम बढ़ा ही नहीं। यह सी०आई०पी०, सेंट्रल इस्यू प्राइस था और चूंकि कीमत नहीं बढ़ाई तो उसके कारण भी दाम बढ़ा गेहूं का। इकोनोमिक जस्टिफिकेशन है यह। चौथा कारण है 31 लाख टन हमारा उत्पादन कम हुआ क्योंकि 653 लाख टन यहां होता था वहां हम 622 लाख टन उत्पादन पर रुक गए। इसके चलते भी मूल्य वृद्धि हुई।

महोदया, सबसे ज्यादा जबरदस्त वृद्धि हुई दो कारणों से, जो मैं लास्ट में दर्द के साथ कहना चाहता हूं और इसमें मैं माननीय सदन के माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहता हूं क्योंकि इसको सामान्य पर ले जाने के लिए मैं कृत-संकल्प हूं। यह शेयर मार्केट की मंदी चल रही थी, तो जो उसकी मनी थी वह मनी चली आई यहां होर्डिंग करने में। उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से वह सारे पैसे लाकर होर्डिंग में लगा दिए। यह जो कालाबाजारी और जमाखोरी के चलते गेहूं के दाम बढ़े हैं, यह आर्टिफिसियल, कृत्रिम मूल्य वृद्धि है और इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। जो रियल मात्रा है इधर, इकोनोमिक जस्टिफिकेशन है। अगर सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि हुई है गेहूं में तो कालाबाजारी, जमाखोरी और जो शेयर बाजार में मंदी चल रही थी उसकी पूंजी यहां डायवर्ट होने से। यह लगभग 28 प्रतिशत चला गया, जो नहीं जाना चाहिए था। यह 20 से नीचे रहना चाहिए था यानि 16 से 20 के बीच फ्लकचुएट करते रहना चाहिए था, लेकिन दाम अस्वाभाविक बढ़ गया और मैं इसको स्वीकार करता हूं।

महोदया, यह दाम बढ़ने के कारण मैंने आपको बताए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं निपटना चाहता हूं ऐसे लोगों से, उसके विषय में भी कहना चाहूंगा। इस देश में कुछ निहित स्वार्थी लोग हैं, वेस्टेड इंटरेस्टेड क्लास के लोग हैं। इस देश में जो कुछ कालाबाजारी करने वाले, जमाखोर लोग हैं वेस्टेड इंस्टरेस्टेड क्लास के लोग हैं, इन लोगों ने एक नेक्सस बना रखा है। उस नेक्सस के जरिए, इस लाबी के जरिए इस देश की आर्थिक व्यवस्था पर समय समय पर उसका कंट्रोल रहता है। आज इसी तरह एक नेक्सस बनाकर के एक साजिश के तहत कृत्रिम अभाव पैदा करके गेहूं का होव्वा पैदा करके पूरे देश में संयुक्त मोर्चे की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे बादल को मैं फाड़ने का काम कर रहा हूं। मैंने फैसला लिया है इस कोहरे को मैं चलने नहीं दूंगा और इसी कारण इसके खिलाफ सरकार ने तुरन्त फैसला लिया। क्या फैसला लिया?...**(व्यवधान)**...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: अभी तक चार महीने से क्यों नहीं किया? इसको भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बिना अनुमति कोई नहीं बोलेगा।...**(व्यवधान)**...आप लोग शांत रहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अच्छा, अभी तक नहीं किया, वह मैं बता देता हूं। जो अभी तक किया है, वह भी सूचना है। महोदया, माननीय सदस्य का कहना है कि अभी तक क्या क्या किया?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): नहीं, आप अपनी बात कहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं अभी तक और आगे तक, दोनों बात आपके सामने, सदन के सामने रख देना चाहता हूं। यह सरकार 25 जून, शुरू से ही सतर्क थी। जबसे मैंने कार्यभार संभाला, उसी समय से मैं सतर्क था, सावधान था। लोग कहते हैं कि समय से कार्यवाही नहीं हुई। ठीक है, आप कागज से जो भी तथ्य दे दीजिए, लेकिन 25 जून के बाद एक छटांक गेहूं का भी निर्यात नहीं हुआ, गेहूं का निर्यात रोक दिया गया।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: आटे का हुआ या नहीं? सितंबर में आटे का किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी, आप अपनी बात कहिए। हरेक का हर मिनट मिनट पर जो भी वह बात करे अगर उसका जवाब आप देते जाएंगे तो यह अनंत कथा चलती ही रहेगी। आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हमें एक-डेढ़ दर्जन माननीय सदस्यों का जवाब देना है। सरकार की तरफ से तो सरकार को अपनी बात कहनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा, 25 जून के बाद गेहूं का निर्यात तक रोका गया, जब मेरे संज्ञान में यह लाया गया। कृषि मंत्रालय एस्टीमेट देखता है, खाद्य मंत्रालय नहीं देखता है, फूड मिनिस्टरी एस्टीमेट नहीं देखती। आज जो यहां सवाल उठे, उसमें कई वित्तमंत्री से संबंधित भी सवाल थे, जैसे मुद्रास्फिति का सवाल माननीय सदस्यों ने उठाया और उत्पादन का भी सवाल उठाया बहुत जबरदस्त ढंग से, तो मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही जायज तरीके से इस सवाल को उठाया। उत्पादन की फिगर, एस्टीमेंट कौन देगा? फूड मिनिस्टरी को कृषि मंत्रालय देगा। बड़े जोर से हल्ला मचा रहे हैं कुछ लोग क्योंकि हमने कुछ नापने की कोशिश की है, सीमा जो लगा दी है न। हमने कालाबाजारियों और जमाखोरों से कहा कि 200 टन से ज्यादा नहीं मिलेगा। उसमें यह अंडरटेकिंग देनी होगी, अरनेस्ट मनी लगेगी उसके बाद भी। पिछले साल उनकी सीमा असीमित थी। पिछली बार जो ओपन सेल होती थी, एक-एक हजार टन दिया जाता था। मेरे रिजीम में 200 टन की सीमा बांध दी गई। यही तो मैंने अपराध किया है। मैंने उनको सीमित किया ताकि गेहूं गरीब, छोटे चक्की वालों को भी मिले। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 25 जून को मैंने यह बंद किया। जहां तक आपने सवाल उठाया वीट प्रोडक्ट्स का, वीट प्रोडक्ट्स के विषय में उसी क्षण, दूसरे दिन हमने एक्शन लिया। वीट प्रोडक्ट्स के लिए उच्च स्तरीय फैसले लेने पड़ते हैं, सभी विभागों की इसमें कमेंट्स और सहमति होती है क्योंकि कामर्स डिपार्टमेंट में कई मंत्रालय जुड़े हैं, उनसे कमेंट्स लेने पड़ते हैं और यह एक सैकिंड की बात नहीं है क्योंकि जो स्टाइल आफ फंक्शनिंग है, जो कंडक्ट है सरकार का, उसको उस प्रोसैस से गुजरना पड़ता है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ओ॰जी॰एल॰ से वीट प्रोडक्ट्स को भी हमने रिस्ट्रिक्टिड लिस्ट में उसी वक्त किया। आज सूचना देना चाहता हूं कि वीट प्रोडक्ट्स भी कुछ दिन पहले कम्प्लीट रूप से बैन हो गए, वीट प्रोडक्ट्स का भी निर्यात नहीं हो रहा है, कुछ-कुछ जो बहुत कम मात्रा में हो रहा था, उस पर

भी रोक लग गई है। वह कुछ ज्यादा मात्रा में नहीं हो रहा था। फिगर तो आप बहुत लोग बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, मेरे पास जो तथ्य हैं, वही मैं बताऊंगा। इतना ही नहीं पूरे देश के चीफ मिनिस्टर्स का कांफ्रेंस हुआ बेसिक नीड्स पर, जो बेसिक नीड्स हैं इस देश की उस पर चीफ मिनिस्टर्स की एक कांफ्रेंस हुई। सी०एम० की कांफ्रेंस में मैंने साफ शब्दों में अपने पी०डी०एस० की बातों को, प्रोजेक्ट को रखते हुए कहा कि इसको हम इसलिए बैन करना चाहते हैं क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हम आधे दाम पर देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमने यह भी कहा कि पी०डी०एस० में जो अनाज दिया जाता है, उसका डाइवर्ज़न होता है राज्यों में। डाइवर्ज़न का मतलब है कि वह थोक व्यापारियों के यहां चला जाता है, होल सैलर के यहां जाकर बिक जाता है और उसकी ब्लैक मार्किटिंग होती है। जून में मैंने कार्यभार लिया, 25 जून को एक फैसला किया, फिर 5-6 जुलाई को ध्यान आकृष्ट किया और 22 जुलाई को मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा। क्या पत्र मैंने लिखा, राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कालाबाजारियों के बारे में, उसकी एक लाइन मैं पढ़ देता हूं। आज वह सवाल उठा रहे हैं कालाबाजारी का। हम शुरू से ही सचेत थे और यदि हम शुरू से सचेत नहीं होते तो आज महंगाई केवल 28 प्रतिशत नहीं होती, उससे और ऊपर बढ़ जाती और वह 41 प्रतिशत से ऊपर चली जाती। मैंने इसमें कोशिश की, मैंने इसमें दिया है। मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा — यह मेरा पत्र है 22 जुलाई का, मैं आपको उसकी कापी दे सकता हूं — मैंने उनको लिखा कि:—

> ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ व्यापारी और अवांछित तत्व आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने व मूल्यों में हेर-फेर करने में लिप्त हैं। मैं सतर्क हूं उसी समय से। आप अपने अधिकारियों और फील्ड कार्यकर्त्ताओं को सचेत कर दें और यदि सुनिश्चित करें कि ऐसी जमाखोरी और हेराफेरी की प्रवृत्ति पर रोक लगे, तो इसके लिए मैं आभारी होऊंगा।

मुख्य मंत्रियों को लिख रहा हूं मैं, सभी मुख्य मंत्रियों को और यूनियन टेरेटरी के सभी प्रशासक और राज्यपालों को। यह जानकारी मुझे मिल रही थी, मैंने दी कि:—

> सरकार सट्टेबाजी, जमाखोरों और चोरबाजारियों के विरूद्ध निवारक और दंडात्मक दोनों तरह की कार्रवाई करने पर बल देती है। आपसे आग्रह है कि ऐसे अपराधियों को फोरन कड़ा दंड मिले, इसका सुझाव भी आप दें।

अंतिम लाइन मैंने दी:—

> अतः मैं आपसे चाहूंगा कि आप जमाखोरों और चोरबाजारियों और इसी प्रकार की अन्य अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): मैडम, प्वाइंट आफ आर्डर।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): No point of order *(Interruptions)* Why you people are shouting? Please keep quiet. *(Interruptions)* Mr. Meena, please sit down.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने यह साफ-साफ लिखा था, राज्यों को लिखा था कि:—

> आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा अन्य संगत कानून, जो विशेषकर चोरबाजारी निवारण अधिनियम 1930, ऐसेंशियल कांमोडिटी एक्ट तथा चोरबाजारी निवारण अधिनियम 1930 के प्रयोग से न झिझकें।

यह मैंने कहा और ऐसे कहा कि आप समय-समय पर हमको इसकी तुरंत जानकारी या सुझाव दीजिए कि और भी कानून में, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में, चाहे उपभोक्ता सर्वेक्षण एक्ट में यदि कोई चेंज करना केन्द्र सरकार को जरूरी है तो राज्य सरकार अपनी-अपनी राय दे दे, हम किसी भी दूरी पर जाने को तैयार है इस एक्ट को कड़ा और कारगर बनाने के लिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी, एक मिनट रूकिए। What is your point of order?

श्री मूलचन्द मीणा: मंत्री जी अपने उस लैटर को पढ़ रहे हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है। यह इतनी बड़ी समस्या है, गरीब लोग, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राईब्ज के लोग भूखे मर रहे है। आप सरकार चला रहे है। यह पत्र लिखकर आप अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। आप जिम्मेदारी लीजिए कि महंगाई बढ़ी है। यह आपकी सरकार की ज़िम्मेदारी है कि महंगाई

कैसे बढ़ गई। आप अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ...(व्यवधान)

THE VICE- CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): There is no point of order.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदया, जब यह बिंदु उठा था तो माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने मेरी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। महोदया, मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को उस समय लिखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानून में अगर कोई भी परिवर्तन करना है तो राज्य सरकारें उसके लिए हमें सुझाव दें ताकि इसके लिए कारगर कदम उठाए जा सकें।

महोदया, कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ मैंने 7 अगस्त, 1996 को सभी स्टेट्स के फूड मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस बुलाई और उनसे कहा कि हम राज्यों को पी०डी०एस० के लिए जो अनाज देते हैं, उसका डाईवर्जन होता है, वह ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता है, उसकी होर्डिंग होती है। इसको आप रोकिए अन्यथा आवंटन करते समय हमें विचार करना पड़ेगा कि हम इतना अनाज आपको दें या न दें। राज्यों के फूड मिनिस्टर्स ने कहा कि इस पर हम लोग ध्यान देंगे। सरकार इस बारे में शुरू से सचेते है।

महोदया, ओपन सेल के विषय में एक खास दल के सदस्य बड़े जोर-शोर से चर्चा उठाते हैं। चर्चा करना उनका अधिकार है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं स्वागत करता हूं उनके विचारों का, लेकिन तथ्यों से परे कोई भी बात उठाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। हम लोग इसी धरती से आए हैं और जनता के लिए समर्पित होकर आए हैं। केन्द्रीय सरकार का इसके लिए कमिटमेंट है। हमारी संयुक्त मोर्चे की सरकार गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करेगी और कभी भी उनके हित की अनदेखी नहीं होने देगी।

पहले जमाने में एफ०सी०आई० के माध्यम से 1993 में गेहूं देने की यह प्रणाली शुरू हुई। बड़ी-बड़ी रोलर फ्लोर मिल्स को हजार टन गेहूं मिलता था। हमें लगा कि यह उचित नहीं है और इस पर रोक लगानी चाहिए। तब हमने स्ट्रीमलाईन किया और तुरंत डॉयरेक्शन भेजी कि 200 टन से ज्यादा गेहूं किसी मिल को नहीं दिया जाना चाहिए। हमने कहा कि 3 आदमियों कि कमेटी बनेगी जिसमें सभी राज्यों के डॉयरेक्टर ऑफ फूड मेंबर होंगे और बाकी 2 मेंबर्स में से एक आई०एम०एम० रैंक का अधिकारी होगा और दूसरा एकाउंट्स का अधिकारी होगा और इसकी हिसाब-किताब की जिम्मेदारी कमेटी पर रहेगी। यदि कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी कमेटी पर होगी। हमने एक तारीख से लेकर सात तारीख तक आवेदन देने का नियम बनाया और कहा कि इसका डिस्पोजल 14 तारीख तक हो जाएगा और किसी को भी 200 टन से ज्यादा गेहूं नहीं मिलेगा। उन लोगों को बड़ी चिंता हो गई कि 200 टन से कैसे काम चलेगा क्योंकि हजार टन लेने की आदत जो पड़ी हुई थी। इस आदत पर हमने चोट की और 50 परसेंट छोटी चक्की वाले और 50 परसेंट बड़ी मिल वाले को हमने गेहूं उपलब्ध कराया।

हम जानते हैं कि हम एकदम इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन करने में समय लगता है। जो हैव्ज़ क्लास है, उससे लड़ने के लिए हमें धीरे-धीरे काम करना पड़ेगा।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: ये सब करने के बाद भी 12 रुपए किलो आटा क्यों बिक रहा है? इन्होंने इतने कदम उठाए फिर भी आटा 12 रुपए किलो में बिक रहा है। मेरे फैसले का जो परिणाम है वह तो

5.00 P.M.

आप सुनिए कि क्या-क्या फैसला लिया। महोदया, उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा कुछ और कारगर कदम उठाने चाहिए। तो मैं अभी क्या फैसला लिया। जब सब राज्यों से अक्तूबर तक हमको राय आ गई, जो 22 जुलाई को मैंने सभी यूनियन टेरिटरी के प्रशासकों और राज्यपालों को चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब अक्तूबर के अंत तक आया। दिल्ली सरकार जवाब नहीं दे रही है। मैंने उनको रिमाइंडर भेजा कि जरा आप भी अपनी राय स्पष्ट कीजिए। मैं आपके राज्य के खिलाफ नहीं हूं। मेरी मुख्य मंत्री जी से बात हो गई। उन्होंने कहा कि — यादव जी, 24 घंटा और रुकिए, मैं जमाखोरों के खिलाफ छापा मारकर दिखलाता हूं। केवल 24 घंटा या कल सुबह तक का समय उन्होंने लिया। आज मैंने सम्पर्क किया। कोई मुख्य मंत्री ने सम्पर्क नहीं किया। इसको रोकिए कालाबाजारी और जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाईए। उनको मैंने सख्ती दिया। राज्यों ने हमें लिखा कि ठीक है, आप तो कहते है कालाबाजारी रोकने के लिए। लेकिन 1994 में 30 सितम्बर को एक आदेश केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से गया था। वह आदेश क्या था—फूडग्रेन कंट्रोल और लाइसेंसिंग आर्डर। उस आर्डर के तहत कोई आदमी

कितना गेहूं और आटा रख सकता है। इसमें पूरी छूट थी। मैंने इसको निरस्त कर दिया और पूरे देश में हर राज्य सरकार को कहा है कि आप जितना लिमिट लगाना चाहते हैं आप अपने राज्य में होर्डिंग और ब्लैक-मार्केटिंग रोकने के लिए लिमिट लगाएं। होल्डिंग लिमिट का नतीजा यह हुआ है महोदया, कि गेहूं के दाम में गिरावट आई है। पहले कहां-कहां छापामारी चल रही है उसकी जानकारी सदन को दे देना चाहता हूं। हरियाणा की आज की रिपोर्ट मैंने ली है, क्योंकि ताजा रिपोर्ट सदन को देना जरूरी है, सदन सर्वोपरि है, मैं आप सब लोगों का सम्मान करता हूं। मैंने कहा कि मैं यहां आज की रिपोर्ट दूंगा। हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सेल खुला हुआ है हमारे मंत्रालय में, यह जो जमाखोर लोग हैं उनको ठीक करने के लिए। हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं। हरियाणा से जो फूड सैक्रेटरी का जवाब आया है—स्टॉक सम्बन्धी निर्देश जारी हो रहे हैं। वह जो होल्डिंग लिमिट वाला है, स्टॉक डिस्प्ले करना है कि कितने दाम पर दुकानदार सामान बेचेंगे, उनको गेहूं, चाय, आटा के दाम की लिस्ट टांगना होगा। कितना अनाज उनके पास है उसकी सूची उनको डिस्प्ले करना होगा, नहीं तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार हो जाएंगे, ज्यादा रखेंगे तब भी गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में आपका नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी होगी। अब चलिए पंजाब में। पंजाब ने बताया है कि स्टॉक लिमिट निर्धारित करने हेतु आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं। लेकिन पंजाब में गेहूं की समस्या इतनी गंभीर नहीं है जितना बताया गया है। वहां गेहूं का मूल्य लगभग 640 रुपए से 650 रुपए प्रति क्विंटल है। एक माननीय सदस्य भी बोल रहे थे। यह तो सरकारी रिपोर्ट है, मेरी तो नहीं है, पंजाब सरकार से आई है। पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि खुले बाजार हेतु वितरित करने वाले गेहूं को वह भारतीय खाद्य निगम से लेकर उसका आटा बनाकर 5 रुपए 80 पैसे की दर से बेचेंगे। यह पंजाब सरकार कह रही है। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि उसने स्टॉक होल्डिंग सीमा निर्देश 16 दिसम्बर को जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के माननीय सदस्य बोल रहे थे और राज्य में कितनी जगह गेहूं के छापे मारे गए उसकी सूचना इकट्ठी करके कल तक केन्द्रीय सरकार को भेजेगी। यह महाराष्ट्र सरकार की बात है। अब राजस्थान में चलिए। राजस्थान से रिपोर्ट आई है कि स्टॉक होल्डिंग सीमा निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और पिछले कुछ दिनों में मूल्यों में 20 से 30 रुपए की गिरावट आई है। जो हमने स्टेप लिए हैं उसका क्या-क्या परिणाम निकल रहा है वह भी साथ-साथ है। सचिव, खाद्य ने यह भी राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम की अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाए ताकि आवश्यकता के अनुसार भारतीय खाद्य निगम गेहूं हमको दे सके। जो बात आई में सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो मिनिस्ट्री के पार्ट में है वह भी बात में आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने सचिव को इस संबंध में पत्र भी लिखा है, प्रोक्योरमेंट के सैक्रेटरी, गवर्नमेंट आफ इंडिया के। दिल्ली का सुनिए। खाद्य आयुक्त, दिल्ली ने बताया कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट संबंधी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। आदेश निर्गत करने के उपरान्त व्यापारियों को निर्धारित लिमिट के अनुसार कार्रवाई करने के लिए समय दिया गया। अब एक-दो दिन पश्चात संपूर्ण छापे मारने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है और यही नहीं, मैंने मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत तौर पर बात की तो मुख्य मंत्री जी ने सिर्फ बारह घंटे का समय मांगा कि बारह घंटे में मैं आपको बताऊंगा, तीन जगह मैं स्टडी कर चुका हूं और मैं तैयार हूं। गेहूं आपने दिया है केन्द्र सरकार ने, हमारी कोई शिकायत नहीं है। यह बयान उनका आ गया है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: क्या उन्होंने यह कहा है कि कोई शिकायत नहीं है? उन्होंने आपको पत्र लिखा है कि 30,000 टन हरियाणा से आप दे रहे हैं। हरियाणा से आप कैसे लाएंगे? उन्होंने आज ही चिट्ठी लिखी है आपको कि 30,000 टन आप हरियाणा से लाएंगे तो 30,000 टन आप कैसे लाएंगे? ...(**व्यवधान**)... आप दिल्ली से क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं आपको बताता हूं। उनके विषय में शुरू में ज़रूर कहा गया था। आप फिर से वेरिफाई कर लीजिए अपनी जानकारी को। मेरी जानकारी थोड़ी लेटेस्ट है। आपके सदन में आने से पंद्रह मिनट पहले की जानकारी है मेरे पास। 35,000 टन उन्होंने मांगा था कि यहीं से दिया जाए तो यहीं से हमारा फूडग्रेन्स का मूवमेंट हो गया है और आज की तारीख में दिल्ली के गोदामों में कुल मिला कर 66,534 टन गेहूं है हमारे पास और जो रिपोर्ट आपको चाहिए, वह भी मैं दे दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र मोहन: मान्यवार केवल यह स्पष्ट कर दें कि जो राज्य सरकारें गेहूं नहीं उठा रही हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): नहीं, आप बैठ जाइए...आप बैठ जाइए। बिना चेयर की इजाज़त के आप कुछ नहीं बोल सकते।

हूं, 48,000 टन, यह अक्टूबर का फिगर है। सितम्बर में 46,000 टन था। क्यों नहीं उठाते हैं, इसके कारणों की भी मैंने जांच की है।...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन: यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं उठाते हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने कहा कि फूड मिनिस्टर हैं श्री लाल बिहारी तिवारी जी। मैंने उनके साथ मीटिंग की थी 3 दिसम्बर को। मैंने पूछा कि क्यों नहीं उठाते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे पास गोदाम नहीं हैं। हमारा ट्रक मूवमेंट एक दिन में इतना नहीं होगा कि हम 2000 टन उठा सकें। तो 2000 टन एक दिन में तो तीस दूनी साठ, तब भी हो जाएगा। 2000 टन नहीं उठा रहे हैं, आजकल 15000 टन उठा रहे हैं। फिर मुख्य मंत्री जी की पहल पर आपको 2000 टन पहुंच गया है। प्रतिदिन हम 2000 टन दे रहे हैं दिल्ली को पी०डी०एस० का। इधर आपका आबंटन थोड़ा बढ़ा है एक-दो दिन से, नहीं तो अभी तक मात्र 48,000 टन दिल्ली को मिल रहा था। अब सारी दुनिया में हल्ला मचा रहे हैं कि दिल्ली को गेहूं नहीं दिया जाता है। मैंने गोदामों की पोज़िशन बताई कि सभी गोदामों में कितना-कितना है। समय ज्यादा लग जाएगा नहीं तो मैं मायापुरी से लेकर ओखला, नरेला, घेवड़ा, आर०पी०बाग, शक्तिनगर सभी जगहों का हिसाब बता सकता हूं कि कितना गेहूं पड़ा हुआ है एफ०सी०आई० के गोदामों में जहां से हम आपको मुहैया कर रहे हैं और हमारा गेहूं का मूवमेंट हो रहा है।

अभी माननीय सदस्य ने ऐलोकेशन की बात कही। तो हम राजस्थान को देते हैं 1,19,000 टन और उठाते हैं 98,000 टन। मध्य प्रदेश को देते हैं 46,000 टन और उठाते हैं 45,000, टन इसकी पोज़िशन अच्छी है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हम पी०डी०एस० का गेहूं तो दे ही रहे हैं, खुले बाज़ार का...और जानकारी आ गई है, खुले बाज़ार का गेहूं भी हम यहीं से दे रहे हैं आपको। आप क्या बात करते हैं? हम जो बात करते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। ...**(व्यवधान)**... केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी में जो भी बात करते हैं, उसका निर्वहन करते हैं पूरी तरह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60,800 टन हम ऐलोकेट करते हैं दिल्ली को। हम दिल्ली पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहते थे, माननीय सदस्य काफी इंटरस्टेड हैं लेकिन पूरे देश की बात यहां हो रही है। 60,000 टन हम प्रतिमाह ऐलोकेट कर रहे हैं। सितम्बर में 60,000, अक्तूबर में 60,000, नवम्बर में 60,000 और दिसम्बर में 60,000। उठाते कितना हैं, महोदया मैं आपको बताता हरियाणा को 16,000 टन देते हैं पी०डी०एस० का जो प्रतिमाह हम देते हैं और उठाते हैं 13.3 हजार टन। गुजरात को देते हैं 53,000 टन और उठाते भी 53,000 टन हैं तो इसकी पोज़िशन अच्छी है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि ये उठा लेते हैं। महाराष्ट्र को 80,000 टन देते हैं और उठाते हैं 70,000 टन, बिहार को देते हैं 58,000 टन और लगभग 45,000 टन उठाते हैं, कर्नाटक को 30,000 टन देते हैं, वह 23,000 टन उठाता है, केरल को 50,000 टन देते हैं और वह उठाता है 49.70 हजार टन, केरल की पोजिशन भी अच्छी है।

श्री नरेन्द्र मोहन: जिन राज्यों की स्थिति खराब है, उन पर क्या ऐक्शन हो रहा है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अब मैं उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं। अभी मैंने केवल मध्य प्रदेश की छापामारी की जानकारी दी थी। उत्तर प्रदेश में अभी तक 14,437 दुकानों का इंसपैक्शन हुआ है और उसमें 57 एफ०आई०आर० हुए हैं। 63 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं होर्डिंग लिमिट से और 1157 दुकानें सस्पेंड हो गई हैं जो होर्डिंग कर रही थी। 731 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और 90,40,156 रुपए की राशि का अवैध गेहूं पकड़ा गया है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो सरकार इच्छा शक्ति से काम करेगी तो जरूर कार्यवाही होगी और मूल्यों पर सरकार निश्चित रूप से नियंत्रण करेगी। इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए। उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। लखनऊ में थोक गेहूं के संबंध में आज ही यह जानकारी मिली है कि लखनऊ में थोक गेहूं का मूल्य 17 तारीख की शाम तक 625 रुपये है, थोक आटे का मूल्य 660 रुपये है। खुदरा गेहूं का मूल्य 650 रुपये और आटे का मूल्य 700 रुपये रिटेल में है। मैंने यह सभी राज्यों की रिपोर्ट आपको बतायी है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात की और जानकारी मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं। यह बात काफी जोर-शोर से माननीय सदस्यों की तरफ से उठायी गयी थी, बहुत जोरों से ऐक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की बात उठ रही थी। मैंने कुछ नये निर्णय भी लिए हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने निर्णय लिया कि किसी भी राज्य को एफ०सी०आई० खुले बाजार में गेहूं नहीं देगा। अब हमारा खेल देखिए, गरीब लोगों के लिए। मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं खुले बाजार का काम आज से बंद करता हूं। अब सभी राज्य सरकारों को एफ०सी०आई० गेहूं देगा लेकिन शर्त यही है कि राज्य सरकारें उसे निश्चित दाम पर बांटें। मैं मंथली मानिटरिंग करूंगा कि जो राज्य सरकारें एक निश्चित दाम बनाकर

आटा, गेहूं के प्रोडक्ट्स और गेहूं की बिक्री करने का काम नहीं करेंगे, उनके आबंटन को रोकने की दिशा में हम पहल कर सकते हैं। यह कंट्रोल भारत सरकार का होगा ताकि राज्य सरकारें निश्चित दामों पर आटा और गेहूं उपलब्ध कराएं। जो गेहूं वह लेना चाहेंगे, जो रिक्वायरमेंट उनका ओपन सेल का होगा, चाहे उनको रोलर मिलों को देना हो, छोटी चक्कियों पर देना हो, कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को देना हो, कन्ज्यूमर इंस्टीट्यूशंस को देना हो, यह उनकी आजादी रहेगी। सभी कलैक्टरों को इस संबंध में हम कमेटी बनाकर गाइड लाइन भेज रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे और कलैक्टर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने जिले में कमेटी बनाकर जो भी वहां की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करेंगे। यह फैसला मैंने लिया है। दूसरा फैसला यह भी लिया है कि जो पी०डी०एस० का 8 लाख 60 हजार मैट्रिक टन हम प्रति माह देते थे, उसको बढ़ाकर 9 से 10 लाख टन अब प्रति माह मुहैया कराएंगे तो मैंने यह फैसला आपको बताया है। पंजाब को तत्काल प्रभाव से जो ओ०एम०एस०एस० के अंदर गेहूं की खरीदगी सीमा के व्यक्तिगत आवेदकों या संपूर्ण राज्य के लिए समाप्त कर दिया गया है बशर्ते पी०डी०एस०, आर०पी०डी०एस० और ओ०डब्ल्यू०एस० यानी वैलफेयर स्कीम्स के लिए जो योजनाएं हैं, उनके अनुसार भंडार सुनिश्चित किए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र मोहन: आपने नयी नीति घोषित कर दी है, इस संबंध में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी ने काफी विस्तार से बताया है। अब कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है ...**(व्यवधान)**... 500 करोड़ रुपये का घोटाला उसमें हुआ। मंत्री जी के उत्तर से हम लोग संतुष्ट नहीं है इसलिए हम वॉक आउट करते हैं।

SHRI VAYALAR RAVI: Mdam. I want to seek one clarification. *(Interruptions)* The hon Minister just saud something which I could not follow. I would like to know what the present supply of wheat to the PDS is and what increase has been proposed in the PDS quota.

THE VAYALAR RAVI: Madam, I want to seek one clarification. What is wrong with you? *(Interruptions)* I am putting this question to you. madam. Please tell me. *(Interruptions)* Interrutions)

THE VICE-CHAIRMAN (Smt. Kamla Sinha): Mr. Minister teh hon. Membert, Mr. Vayalar Ravi could not follow you. You can reply to his clarification. *(Interruptions)*

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, why are you objecting to my seeking a clarification from him? *(Interruptions)* what is this? I want a clarification. *(Interruptions)* I havae a right to seek clarification. *(Interruptions)*

श्री गया सिंह (बिहार): बोल दिया है, आप उस समय हदाउस में नहीं थे। ...(व्यवधान)..

श्री नवेश यादव: हुम का समय बर्बाद नहीं किया जाए। मंत्री जी बोल चुके हैं। ...(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (Smt. Kamla Sinha): Mr. Vayalar Ravi, don't get angry. Kindly take your seat. *(Interruptions)*

SHRI VAYALAR RAVI: madam, this is not fair.

श्री नरेश यादव: जमाखोरों पर रोक लग गयी, क्या इसलिए संतुष्ट नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**... (इसके पश्चात कुछ माननीय सदस्यों ने सदन का त्याग किया।) I just want to seek a clarification. *(Interruptions)*...

SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV: Kindly listen to me. *(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: What is wrong in seeking a clarification? *(Interruptions)*... I want to seek a clarification. You don't want to give clarification. *(Interruptions)*... Then why do you shout at me? *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Vayalar Ravi, don't get angry. *(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: I don't get angry. *(Interruptions)*... I have a right to seek a clarification. *(Interruptions)*... What is wrong with you? You keep quiet. *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Vayalar Ravi, since you didn't follow him he is going to tell you. Kindly take your seat. *(Interruptions)*...

SHRI SAIFULLA (Andhra Pradesh): Nobody is shouting. Unfortunately, my friend has come now. *(Interruptions)*... The Minister is answering. *(Interruptions)*... The Minister is answering. *(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: I have a right to seek a clarification. *(Interruptions)*... I have a right. *(Interruptions)*...

SHRI SAIFULLA: Madam, he has got a right. The Minister will answer. *(Interruptions)*...

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA (Rajasthan): Madam, the thing is that he couldn't follow Hindi. He is seeking a clarification. *(Interruptions)*... Why do they shout at him? *(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, I want to seek one clarification. *(Interruptions)*... The hon. Minister just said something which I could not follow. I would like to know what the present supply of wheat to the PDS is and what increase has been proposed in the PDS quota. *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): The Minister has given it in detail. *(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, I want to seek one clarification. What is wrong with you? *(Interruptions)*... I am putting this question to you, Madam. Please tell me. *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Minister, the hon. Member, Mr. Vayalar Ravi could not follow you. You can reply to his clarification. *(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, why are you objecting to my seeking a clarification from him? *(Interruptions)*... What is this I want a clarification. *(Interruptions)*... I have a right to seek clarification *(Interruptions)*...

श्री गया सिंह (बिहार): बोल दिया है, आप उस समय हाउस में नहीं थे। ..**(व्यवधान)**..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी आप बता दीजिये इनको। इनको जो जानकारी चाहिये, आप बता दीजिये। ...**(व्यवधान)**

SHRI VAYALAR RAVI: What do you think? You can shout at me! *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): Mr. Vayalar Ravi, the Minister is answering. *(Interruptions)*...

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, I politely sought a clarification. They shouted at me. This is how the ruling party Members behave. *(Interruptions)*... I can deal with you. *(Interruptions)*... You don't threaten me. *(Interruptions)*... Don't talk. *(Interruptions)*... I know what you are. *(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): कृपया शांत रहिये। मंत्री जी, इनको बता दें, इनके आने से पहले क्या हुआ, वे यह जानना चाहते हैं।

SHRI VAYALAR RAVI: No, I don't want any clarification. I am sorry. I withdraw my question. *(Interruptions)*...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: रवि जी ने जो सवाल यहां उठाया, मैं समझता हूं कि आपकी अनुमति है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): जब आपने सदन को बताया था तो ये सदन में नहीं थे। ये सदन में देर से आये हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जब चेयर की अनुमति है, आसन की अनुमति है तो मैं निश्चित रूप से इस विषय में अपनी राय बता दूंगा। जो इंक्रीज हुआ आठ लाख साठ हजार, ऐट लाख सिक्सटी थाउजेंड पर-एलोकेशन हम आल ओवर इंडिया सम्पूर्ण देश में सभी स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरी को देते हैं। अभी तक जो व्यवस्था थी उसमें पांच हजार, छः हजार कभी किसी महीने हमने फैस्टीवल के चलते बढ़ाया लेकिन अभी हमने उसको अक्तूबर में बढ़ाया था 4.31 लाख जब मैंने कार्यभार संभाला था। अभी जनवरी, 97 में मैंने तय कर लिया है

कि इसको अब बढ़ाकर 9.16 लाख टन कर दिये पूरे आल आंवर इंडिया में नो लाख सिक्सटीन थौंड्रिक टन वीह्ट्स को पीडीएस में हमने अब कर दिया है।...(**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I want just one minute. It is a very important question. I am not quarelling with the Minister. I want an assurance from the Minister because the southern States, Pondicherry, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala, have been affected by flood, hurricane and cyclone. These States need more allocation for distribution through the PDS to help the people. There was a torrential rain for 25 days. I want an assurance from the hon. Minister that when the States approach him they would be given foodgrains liberally.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी इन्होंने बताया कि दक्षिण के प्रांत आंध्र प्रदेश, पोंडिचेरी, केरल, तमिलनाडु आदि में तूफान, बाढ़ के कारण बहुत परेशानी होती है। क्या आप वहां राशन बढ़ाने वाले हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: माननीय सदस्य ने बहुत ही उचित सवाल उठाया है। कहीं नेच्युरल कैलामेटीज होती है, कहीं प्राकृतिक आपदायें आती हैं, फ्लड्स आ जाती है, साईक्लोन आ जाता है। अभी हमने आंध्र का किया, उड़ीसा का किया इसीलिए माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह बिल्कुल उचित है। निश्चित रूप से समय-समय पर ऐसी स्थिति आने पर विशेष आबंटन उन राज्यों को दिया जायेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जीरो आवर होगा।

RE: MASSACRE OF TWENTY-FIVE PERSONS IN KALYANPUR POLICE STATION AREA OF TRIPURA

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Madam Vice-Chairman, since independence the entire North-East including Tripura has been chronically neglected in infrastructure. Tripura doesn't have even a railway network. As a consequence there is large-scale unemployment and there is hardly any industry in Tripura. Weapons raided the village at midnight and opened fire indiscriminately. They killed the people and burnt their houses. These ultras did not spare even the children. They lifted a three-year old child from the lap of her mother and shot him dead. This is the worst ever massacre after the Mandai riot which occurred in 1980. Sir, the people of Tripura have lost faith in the Left Front Government which has failed to protect the lives and properties of the people. The incident of Kalyanpur is not the only incident. Everyday untoward incidents are taking place in the State. Kidnapping of people for ransom has become a day-to-day phenomenon. There are also reports of raping a number of women in the hilly areas. When the situation is so alarming, the Government has become a mute spectator. The Government has suspended the officer in charge of Kalyanpur police station after the incident and instituted a CID inquiry. But the people have no faith in the State administration. I strongly demand a CBI inquiry into the incident.

Maybe, Tripura is in the farthest corner of the country. Tripura is always neglected by the Central Government. I am referring to all this because the people of Tripura are working overtime to unite the tribal and non-tribal people in the State. The Central Government should lend all material support to complement the efforts of the people of Tripura. I am referring to all these in the background of a massacre of 25 people, a few days back, at Kalyanpur of West Tripura. That was a ghastly incident. All of us know about it.

Madam, four battalions of the BSF and 10 companies of the CRPF were withdrawn from the State for other national exigencies. Three battalions of the Assam